विक्रम संवत् 2081 ▪ श्रावण /भाद्रपद मास(06) ▪ 01 अगस्त 2024 ▪ मूल्य : 23 रु.

आर.एन.आई. पंजीयन क्र.017261/69, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/297/2024-26, पृष्ठ संख्या-44, प्रकाशन दिनांक प्रत्येक माह की 10 तारीख, पोस्टिंग प्रत्येक माह की 15 एवं 20 तारीख

चरैवेति

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

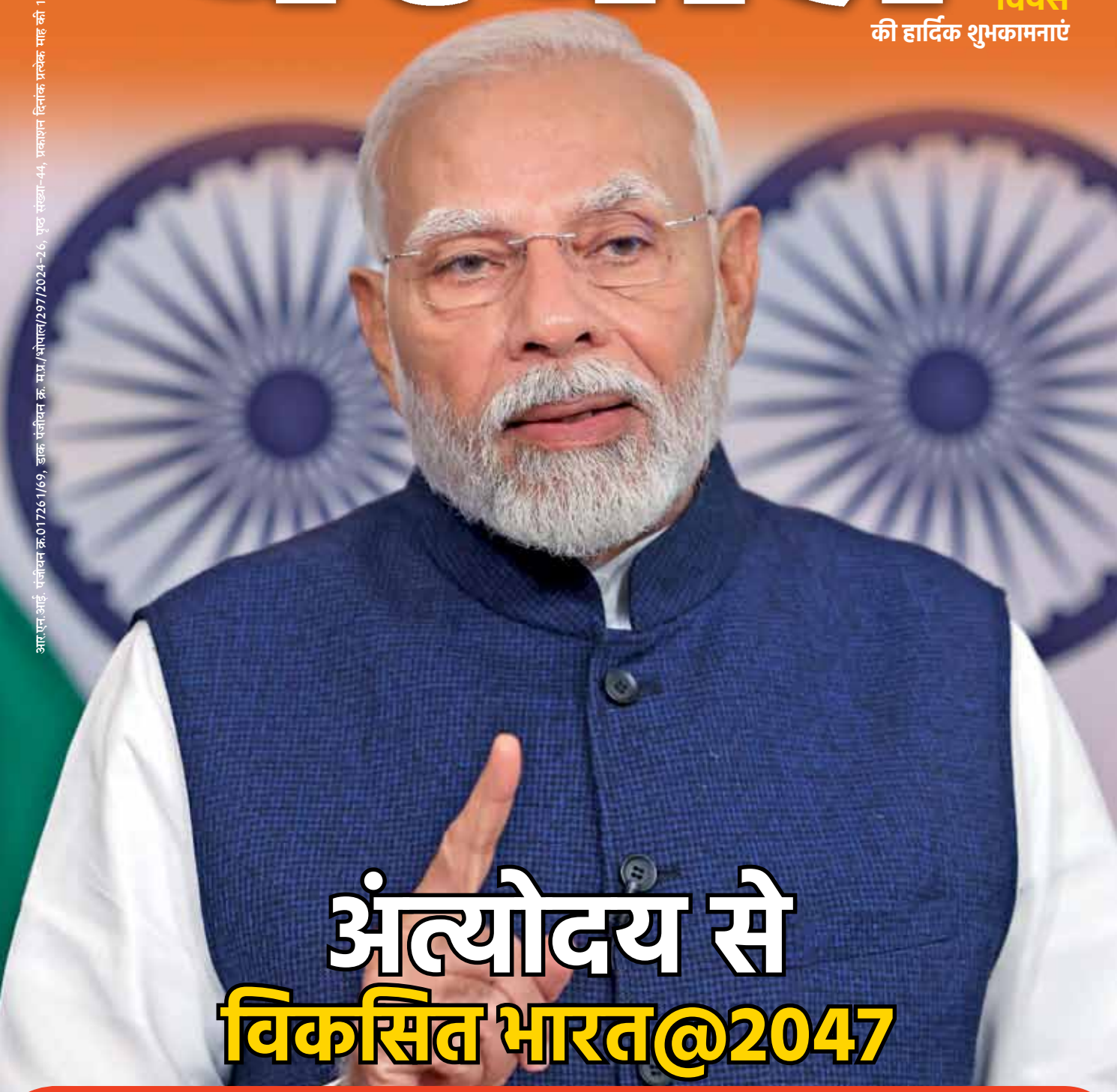

अंत्योदय से विकसित भारत@2047

» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित किया गया।

» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की।

» केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मोदी 3.0 का पहला केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया।

» भाजपा अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

» भाजपा अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी ने रथ यात्रा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया।

» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा भाजपा अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी ने बीजेपी मुख्यालय में "स्नेह मिलन" कार्यक्रम में भाग लिया।

» प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टी-20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी।

» प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा भाजपा अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी ने भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया।

अनुक्रमणिका

संपादकीय • संजय गोविन्द खोचे 04

- विकसित भारत का मजबूत आधार तैयार

कवर स्टोरी • अखिलेश जैन, सी.ए. 05

- अंत्योदय से विकसित भारत@2047

- **विकसित भारत@2047 :** 08
  - » विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट - प्रधानमंत्री
  - » जनहितैषी और विकास हितैषी बजट : अमित शाह
  - » विकसित भारत बनाने का बजट : विष्णुदत्त शर्मा
- **ऐतिहासिक बजट :** 14
  - » प्रदेश का बजट - सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है...
- **ऐतिहासिक बजट :** 15
  - » मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा व ऐतिहासिक बजट- विष्णुदत्त शर्मा
- **भरोसे की जीत :** 16
  - » संकल्पों को सिद्ध करने के लिए चुना है : पीएम मोदी
- **एक पेड़ माँ के नाम :** 23
  - » 'एक पेड़ माँ के नाम' अब पूरे देश में जनआंदोलन - अमित शाह
- **जनता का भरोसा :** 25
  - » तीसरा टर्म मतलब तीन गुना स्पीड - पीएम मोदी
- **मन की बात :** 32
  - » 'हर-घर तिरंगा' से गर्व का अनुभव
- **जयंती :** 36
  - » वीरांगना रानी अवंती बाई
- **पुण्यतिथि :** 37
  - » नारी शक्ति की प्रतीक हैं देवी अहिल्या
- **शहीद दिवस :** 38
  - » क्रांतिवीर मदनलाल ढींगरा
  - » खुदीराम बोस
- **पुण्यतिथि :** 40
  - » वाह रे वकील-वाह रे मुवक्किल
- **विचार प्रवाह : पं. दीनदयाल उपाध्याय** 41
  - » कांग्रेस बनाम जनसंघ

• मुख्य व्रत-त्यौहार

1. प्रदोष व्रत 2. शिव चतुर्दशी व्रत 4. हरियाली अमावस्या, स्नानदान श्राद्ध अमावस्या 6. चन्द्रदर्शन, सिंधारा दोज 7. मधुश्रवा, हरियाली तीज, स्वर्ण गौरी व्रत, झूला प्रारम्भ 8. दूर्वा/विनायकी चतुर्थी व्रत 9. नागपंचमी 15. पुत्रदा (पवित्रा) एकादशी 17. प्रदोष व्रत 19. रक्षाबन्धन, स्नानदान व्रत, श्रावणी, नारियल पूर्णिमा 22. कजरी, सतवा तीज, बहुला, गणेश चतुर्थी व्रत 24. गोगा पंचमी, भाई-भिन्ना 25. हरछठ (हलषष्ठी) व्रत 26. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत 27. गोगा नवमी 29. जया/अजा एकादशी व्रत 30. ओमद्वास, बछबारस 31. प्रदोष व्रत

• मुख्य जयंती-दिवस

4. स्वामी अखंडानंद सरस्वती जयंती 9. विश्व आदिवासी दिवस, अंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, कवि. सुभद्रा कुमारी चौहान जयंती 11. खुदीराम बोस शहीद दिवस 14. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 15. योगी अरविंद जयंती 16. पं. अटलबिहारी वाजपेई पु. ति. 19. विश्व छायांकन, संस्कृत दिवस 25. श्री धरणीधर जयंती 29. हाकी जादूगर ध्यानचंद जयंती

वर्ष-56, अंक : 06, भोपाल, अगस्त 2024

हमारे प्रेरणास्रोत

पं. दीनदयाल उपाध्याय

ध्येय बोध

समृद्धि का आधार धर्म है। इस संबंध में हम पाते हैं कि हमारा आधार धर्म, अभावात्मक नहीं है। हमारे यहां अभाव का नहीं संयम का विचार किया गया है। सादा जीवन का विचार किया गया है, धन पैदा किया तो उसका उपयोग धर्मानुसार करना चाहिए।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

सचिव, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
संजय गोविंद खोचे*

सहायक सम्पादक
पं. सलिल मालवीय

व्यवस्थापक
योगेन्द्रनाथ बरतरिया
मोबा. नं. 09425303801

पं. दीनदयाल विचार प्रकाशन म.प्र. के लिये मुद्रक एवं प्रकाशक संजय गोविंद खोचे द्वारा पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 से प्रकाशित

एवं एम. पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेस-II, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा - 201 305 से मुद्रित.

संपादकीय पता
पं. दीनदयाल परिसर,
ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016
e-mail:charevetibpl@gmail.com
web site:www.charaiveti.org

मूल्य- तेईस रुपये

*समाचार चयन के लिए पी.आर.बी.एक्ट के तहत जिम्मेदार

2014 की कांग्रेस सरकार से अगर मोदी सरकार की तुलना की जावे तो भारत का रक्षा बजट 2024-25 में दोगुना हो चुका है। रेल का बजट 8 गुना से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों का बजट 8 गुना हो चुका है। कृषि का बजट 4 गुना से अधिक बढ़ाया जा चुका है। जिस स्पीड व स्केल से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। मोदी सरकार ने सभी पहलुओं व सभी वर्गों का समुचित विकास किया है।

विकसित भारत का मजबूत आधार तैयार

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तब भारत विश्व में 11 वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और 10 वर्षों के भाजपा शासनकाल में भारत विश्व में पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। कांग्रेस शासनकाल में 2014 में भारत सरकार का बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का था और 10 वर्षों के अंतराल के बाद मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत 2024-25 का बजट 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 2004 में जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी तब कांग्रेस की सरकार के पहले बजट में भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) लगभग 90000 करोड़ रुपए का था। 10 वर्ष की कांग्रेस सरकार के उपरांत 2013-14 में भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का था अर्थात् 10 वर्षों के शासन के उपरांत 2.22 गुना की वृद्धि हुई, वो भी विश्व के महानतम अर्थशास्त्री जी कर पाए थे। 2014 में भाजपा ने सरकार संभाली और 2024-25 के बजट में भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) लगभग 11,11,111 करोड़ रुपए का है। सोचिए कहां 10 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल में 2.22 गुना की वृद्धि और भाजपा के श्री नरेन्द्र मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई।

इसी तरह और पहलुओं को देखें तो आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े सार्वजनिक हैं।

2014 की कांग्रेस सरकार से अगर मोदी सरकार की तुलना की जावे तो भारत का रक्षा बजट 2024-25 में दोगुना हो चुका है। रेल का बजट 8 गुना से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों का बजट 8 गुना हो चुका है। कृषि का बजट 4 गुना से अधिक बढ़ाया जा चुका है। इस तरह बहुत सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा अधिक नहीं हुई है, या चर्चा में आ नहीं पाए। जिस स्पीड व स्केल से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। मोदी सरकार ने सभी पहलुओं व सभी वर्गों का समुचित विकास किया है।

कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष और भाजपा सरकार के 10 वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारी फर्क मिलता है। पहले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तुष्टिकरण व वोट बैंक की पराकाष्ठा थी। भगवान श्रीराम जी के अस्तित्व को नकार देते थे। रामसेतु को तोड़ने का प्रयास करते थे। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। आतंकवादी प्रधानमंत्री जी के अतिथि होते थे। भारतीय सेना पत्थर खाती रहती थी, पर हाथ-बंद करके रखे जाते थे। बम-ब्लास्ट साधारण घटना थी। लाखों करोड़ों के घोटाले बहुत ही सामान्य घटना थी। गठबंधन की पार्टियां दाएं-बाएं ना हो जायें तो उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का भय दिखा कर गठबंधन में रहने को मजबूर किया जाता था। विकास, उन्नति, निवेश, रोजगार, ईमानदारी, युवाओं का भविष्य, महिला सम्मान की तो चर्चा भी निरर्थक है- तंदूर में महिलाएं जलाई जाती थीं। शिक्षा, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और कृषि, आर्थिक स्थिति, आत्मनिर्भरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य यह सब तो चर्चा में भी नहीं आते थे। घोटाले, निराशा, तुष्टिकरण और राज परिवार के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी का नतमस्तक होना जरूर चर्चा के केंद्र बने रहते थे।

अब मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार के 10 वर्षों की चर्चा करें तो स्वच्छता, जनधन योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, तीन तलाक से मुक्ति, धारा 370 का उन्मूलन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 46.92 करोड़ लोगों को ऋण स्वीकृत, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत 2.12 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्शन, 3785308 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में बिना कट के स्थानांतरित, जीएसटी लागू होने के बाद अब तक 9406061 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर स्वीकृत, वा तीन करोड़ नए घरों की और मंजूरी, भारत में भी अब 134933 स्टार्टअप हो सकते हैं, 71604 अमृत सरोवर बन चुके हैं, उज्ज्वला योजना में 103333633 रसोई गैस के कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, 11.57 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है, 14.97 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज, गरीबों का 5 लाख तक का फ्री इलाज, देश का कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा नहीं जहां बिजली नहीं पहुँची हो, वन नेशन वन राशन कार्ड, रेल्वे का कायाकल्प, मेडिकल कालेजों का निर्माण, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 12000 जन औषधि केन्द्र जहां 80 प्रतिशत तक सस्ती दवाऐं मिलती हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आपदा भी अवसर में बदली जी सकती है, कोविड की महामारी में देश को सफल नेतृत्व प्रदान किया गया, 140 करोड़ लोगों को तो स्वदेशी वैक्सीन फ्री मिली, साथ-साथ 100 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जब विश्व के ताकतवर देशों की अर्थव्यवस्था सांसें भर रही थी तब भी विदेशी निवेश भारत के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ा था, वैश्विक आपदा के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से पांचवें नंबर पर आ गई, तुष्टिकरण गायब हो गया, संतुष्टीकरण आ गया, राज परिवार के लिए जनादेश कोने में बैठने का मिला और गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन गया, बहुत फर्क है दोनों सरकारों में। तभी तो 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश मोदी जी को मिला। यह जनादेश संगठन, सरकार व गठबंधन पर जनता का भरोसा है, आशीर्वाद है, जो भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा जनादेश और कई गुना ज्यादा तेजी से काम करने का है और 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के साथ-साथ 2047 तक विकसित भारत बनाना ही देश का लक्ष्य है। यही स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सेनानियों, परिवारों को भारत की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ▪

(संजय गोविन्द खोचे)
सम्पादक

अंत्योदय से विकसित भारत@2047

अखिलेश जैन, सी.ए.

गंभीर दार्शनिक एवं गहन चिंतक, जिन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत सुचिता एवं गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किये। 21 सितंबर 1951 को भारत की राजनीति को महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि राजनीति को नई दिशा देकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की अध्यक्षता में जनसंघ की स्थापना करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को मूल मंत्र मानकर चल रही भाजपा का लक्ष्य **विकसित भारत@2047**, धीरे-धीरे आकार लेने लगा है।

भाजपा, 1996 की 13 दिनों की सरकार के बाद,19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक तथा 26 मई 2014 से लगातार देश के बागडोर संभाल रही है। निश्चित ही देश की सरकार चला रहे राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा, विजन तथा लक्ष्य होते हैं और समय के साथ अपने नए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। भाजपा की नीतियों में ''**अंत्योदय**'' का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो भाजपा सरकारों की आर्थिक नीतियों, बजटों, निर्णयों में परीलक्षित होता है। भाजपा ने अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता किए बिना **विकसित भारत@2047** का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अब भाजपा की योजना क्या है?

विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह प्रति व्यक्ति की आय को 1.25 लाख रूपये प्रति माह तक पहुंचाया जाए? भारत की जीडीपी में अभी औद्योगिक हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है। इसे कम से कम जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा पाना है अर्थात् औद्योगिक हिस्सेदारी को 2047 की जीडीपी में आज की हिस्सेदारी से कम से कम 7.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत तक बढ़ाना है। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था 3.36 ट्रिलियन डॉलर

गंभीर दार्शनिक एवं गहन चिंतक, जिन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत सुचिता एवं गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किये। 21 सितंबर 1951 को भारत की राजनीति को महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि राजनीति को नई दिशा देकर...

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की अध्यक्षता में जनसंघ की स्थापना करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को मूल मंत्र मानकर चल रही भाजपा का लक्ष्य **विकसित भारत@2047,** धीरे-धीरे आकार लेने लगा है।

को लगभग 9 गुना वृद्धि करना होगा अर्थात 23 वर्षों की अवधि में देश के अर्थव्यवस्था को 9 गुना बढ़ाना है। यह कोई आसान काम नहीं है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना है। प्रतिद्वंदी हमारा कोई नहीं है। लक्ष्य हमने स्वयं निर्धारित किया है। बहुत बड़ी चुनौती हमने स्वयं अपने को दी है। तो चुनौती स्वीकार करने से पहले, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योजना भी बनाई होगी।

तमाम प्रश्नों का उत्तर भाजपा का ''**अंत्योदय**'' का सिद्धांत है। चाहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार हो या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। दोनों सरकारों के कार्यक्रमों, नीतियों व आर्थिक सिद्धांतों का

विश्लेषण करें तो केंद्र बिंदु ''**अंत्योदय**'' ही मिलता है।

पहले चर्चा स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की करें तो श्री अटल जी की सरकार ने मार्च 1998 में सत्ता संभालने के मात्र दो माह पश्चात परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। जाहिर है परमाणु परीक्षण के साथ-साथ भारत ने श्री अटल जी के नेतृत्व में देश को न्यूक्लियर पावर स्टेट घोषित कर दिया। कांग्रेस के समय परमाणु परीक्षण करने की तो सभी तैयारी वैज्ञानिक कर चुके थे पर अमेरिका के दबाव के चलते कांग्रेस सरकार परमाणु परीक्षण की अनुमति देने से घबराती रही। हाथ में हाथ रखकर अमेरिका के डर से कांपती रही या कांग्रेस सरकार में भारत के निर्णय अमेरिका के रुख पर निर्भर थे। अटल जी ने देश हित सर्वोपरि रखकर देश को न्यूक्लियर पावर स्टेट घोषित करने में देरी नहीं करी। जबकि 1998-1999 में पूर्वी एशिया के देशों की जीडीपी में तेज गिरावट जारी थी। जापान जो विश्व की पांच प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं में से एक देश था। मंदी के दौर से गुजर रहा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन का असर रूस की आर्थिक स्थिति को तोड़ चुका था। ग्लोबल जीडीपी में 2 प्रतिशत की गिरावट थी। बेहद गंभीर मोड़ की अर्थव्यवस्था के सामने भारत ने परमाणु परीक्षण किया। जिसका परिणाम हुआ कि ताकतवर देशों ने, आर्थिक रूप से संपन्न देशों से भारत पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाये गये। नई आर्थिक चुनौतियां आईं। उस समय कि सरकार, गठबंधन की सरकार थी। चुनौतियों के ऊपर चुनौतियां पर चुनौतियों को चुनौती देकर 2004 में आर्थिक चुनौतियों से मुक्त भारत अटल जी ने कांग्रेस को सौंपा था।

तमाम चुनौतियों के बावजूद देश के रक्षा तंत्र को परमाणु शक्ति संपन्न के रक्षा कवच से मजबूत किया। परिणाम यह हुआ भाजपा ने स्वतंत्र देश के रूप में निर्णय लेकर सारे देश को एकजुट किया। शांति की स्थापना की।

देश नें अंत्योदय के निर्णय लेना प्रारंभ कर दिये। भारत को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिसमें चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया। गांव- गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू कर देश में आर्थिक विकास को तेज रफ्तार दी। गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारा। गरीब को गरीबी से उपर उठाया। देश अपने आप उठने लगा। टास्क फोर्स बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर नदियों को जोड़ना प्रारंभ किया। सूखे और बाढ़ से देश को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। दोनों ही स्थितियां गरीब को और पीछे धकेलना का काम करती हैं। गरीब को गरीबी से बचाने व सहारा देने का प्रयास प्रारंभ किया गया। हर खेत तक पानी, पीने का स्वच्छ पानी, पशुपालन के लिए पानी, उद्योग धंधों के लिए पानी। यह सभी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए सहायक बनी।

गरीबों को प्रगति की दौड़ से बाहर रखने में बहुत बड़ा योगदान जानकारी का अभाव भी होता है। वाजपेयी जी समझ गए थे गरीब को दौड़ लगाने के लिए समय पर सूचना पहुंचाना वो भी सस्ती दरों पर सूचना पहुंचाना बहुत जरूरी है। बीएसएनल का एकाधिकार समाप्त कर नई टेलिकॉम नीति लागू की गई। सस्ते मोबाइल फोन जो गरीब की पकड़ में हो लाकर सूचना की क्रांति लाकर गरीब को विश्व से जोड़ा गया। गरीब के लिए प्रगति का मार्ग बनाया गया। आज की सूचना क्रांति में वाजपेयी जी का यह निर्णय मील का पत्थर बना।

कांग्रेस शासनकाल की देन थी- गरीब और गरीब, अमीर और अमीर।

वाजपेयी जी की भाजपा सरकार ने गरीब को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने रहने से बाहर निकालने के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा कर अति गरीब व गरीब बच्चों के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास प्रारंभ किया। जिससे गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आए और आने वाली पीढ़ियां गरीबी रेखा से ऊपर जाएं।

आतंकवाद देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डालता है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार वाजपेयी सरकार में प्रारंभ हुआ। पोटा कानून लागू किया गया। आर्थिक रफ्तार पर कोई भी प्रहार देश के गरीब को और पीछे धकेलता है। आतंकवाद पर प्रहार मजबूती से किया गया। 32 संगठनों को पोटा के तहत पाबंदी लगाई गई पर दुर्भाग्य से 2004 की मनमोहन सरकार ने पोटा कानून को निरस्त कर देश और देश के गरीबों के साथ न्याय नहीं किया। सारे प्रयासों से वाजपेयी सरकार ने गिरती अर्थव्यवस्था से सम्हली हुई अर्थव्यवस्था दी, विश्व में नवें नंबर की अर्थव्यवस्था के साथ देश 2004 में मनमोहन जी को सोंपा। 11वीं अर्थव्यवस्था का देश 9 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया।

मनमोहन जी 9 नंबर की अर्थव्यवस्था को वापस 11 नंबर के अर्थव्यवस्था पर लाकर छोड़ गए। अर्थव्यवस्था गिरने का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भरता है तो वह अत्यंत गरीब, गरीब व मध्यमवर्गीय भरता है। उनकी अर्थव्यवस्था और पीछे चली जाती है और फिर आगे आने का भरोसा ही टूट जाता है। उनका अपने भाग्य पर विश्वास ही टूट जाता है।

टूटा हुआ भरोसा, टूटा हुआ विश्वास, डूबती हुई अर्थव्यवस्था के बीच गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आशा की किरण बनकर उनके जीवन में एक नया सबेरा हुआ, जैसे उनके जीवन को संभालने के लिए प्रकृति ने उनके साथ न्याय किया हो। मनमोहन जी की विदाई हुई। 26 मई 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को ध्येय मान कर चलने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय मोदी जी ने देश की बागडोर, देश के गरीबों, मध्यम वर्ग के परिवारों के आदेश पर सम्हाली।

मोदी सरकार ने सरकार बनते ही बिना समय गंवाए तेजी से फैसले लेना शुरू किये।

वित्तीय समावेशन, गरीबी दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की जनसंख्या के बड़े हिस्से के लोगों का वित्तीय सेवाओं से दूर रहना गरीबों के साथ, देश की उन्नति में, विकास में बाधक होता है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त 2014 से शुभारंभ कर गरीबों को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्ति का त्यौहार मनाया। अब अंत्योदय ही देश का मूल मंत्र है। अंत्योदय ही देश के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का मूल मंत्र है।

आजादी के 67 साल बाद भी देश की अधिकतर आबादी का बैंक में खाता भी नहीं था। कांग्रेस को इस बात का उत्तर देना पड़ेगा क्या गरीबों की आर्थिक उन्नति का यह दरवाजा 85 पर्सेंट कमीशन के बंटवारे के लिए बंद करके रखा गया था? आज मोदी सरकार के सहयोग से 526400000 अर्थात् 52 करोड़ 64 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अब दिल्ली से भेजा पैसा सीधे हितग्राही के खाते में जाता है। कोई कट नहीं, कोई देरी नहीं, कोई अविश्वास नहीं, कोई अनुनय विनय नहीं।

पिछले 10 वर्षों में 52 करोड़ 64 लाख गरीबों को बैंक में खाता खुलवाकर, देश की मुख्य धारा में लाकर, गरीबों में विकास की संभावनाएं जागृत की गईं। गरीबी में गुजर बसर करने वाले 52 करोड़ 64 लाख लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने की अगर कोई आर्थिक नीति बना सकता है तो यह केवल पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत को मानने वाले मोदी जी ही बना सकते हैं, यह सब भाजपा सरकार में ही संभव है।

25 जून 2015 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मोदी सरकार ने वह सहारा दिया जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम ना था। उन्होंने कभी खुद की पक्की

छत, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, पीने का स्वच्छ पानी, यह सब किसी सपने से कम ना था, कईयों ने तो यह सपना देखने का साहस भी नहीं उठाया था। अंत्योदय के सिद्धांत से विकसित भारत, मोदी सरकार का लक्ष्य, गरीबों को भी सम्मान के साथ, आराम की जिंदगी, बड़ा बदलाव लेकर आया। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 29467085 घरों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 11864000 घरों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इतने घरों की खुशी अंत्योदय के सिद्धांत पर बजट बनाने वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है।

यह भाजपा सरकार की तरफ से गरीबों को गिफ्ट है।

8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा ने भ्रष्टाचार से कमाई गई अकूत संपत्ति,नकली नोट पर करारा प्रहार किया। काले धन की ताकत को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया गया। देश का गरीब परेशान नहीं हुआ। क्योंकि गरीब के पास काला धन था ही नहीं। भ्रष्ट व्यवस्था हैरान परेशान हो गई 15.41 लाख करोड़ रूपया जो अमान्य घोषित किए गए थे उसमें से 15.31 लाख करोड़ रूपया बैंकों में वापस आया बचा हुआ काला धन बक्सों में ही दबा रह गया। कैशलेस या डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला। पारदर्शी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।

घरों में रखा रुपया बैंकों में आया। अर्थव्यवस्था को गति मिली। काले धन की नकली मुद्रा के प्रचलन पर रोक से गरीब को सहारा मिला। सारे आर्थिक विश्लेषणों के बाद एक तर्क सर्वमान्य है, बैंकों में आए पैसे से सरकार गरीब कल्याण योजनाओं को और मजबूती से लागू करने में सफल रही, डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिला, सरकारी कार्यों का दायरा बड़ा और सरकार विकास करने में सफल रही। विकास के लिए उपलब्ध धन किसी न किसी तरह गरीबों की झोली में आया। गरीबों को आर्थिक सक्षमता प्रदान करने में सफलता मिली। नोटबंदी, काले धन पर कड़ा प्रहार था। काले धन पर प्रहार गरीबों के लिए नया अवसर लेकर आया। हर दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ गरीबों को हुआ। गरीबों को सरकार का सहारा मिल रहा है तभी तो अंत्योदय का सिद्धांत सिद्ध हो रहा है।

1 जुलाई 2017 को जीएसटी ने भारत सरकार व राज्य सरकारों के करों के तमाम मकड़ जालों को ध्वस्त कर के एक कर एक रूप, एक समान कर व्यवस्था का रूप लिया। एक राष्ट्रीय कर के फार्मूले पर देश आगे बढ़ा। तमाम करों की वसूली के आड़ में चलने वाला भ्रष्टाचार गायब हो गया। छोटे व्यापारियों को व्यवसाय में बड़ी सुगमता का एहसास हुआ। गरीब और अत्यंत गरीबों के छोटे-छोटे व्यवसायों को सीमा निर्धारित कर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। गरीबों के लिए व्यापार सुगम बनाया गया। करों की चोरी रोक कर राज्यों को धन की उपलब्धता मिली। केंद्र व राज्य के खाते में धन आया। फिर गरीब कल्याण व विकास को धन भेजा गया। फिर गरीब की झोली में धन आया। गरीब की गरीबी कम करने में मदद मिली। अंत्योदय का सिद्धांत सफल सिद्ध हुआ।

इस तरह मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट की नीतियों, विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं, उपलब्धियां का कितना भी विश्लेषण करें, किसी भी निर्णय का विश्लेषण करें, उसका वास्तविक लाभार्थी गरीब ही होता है। जैसे तीन तलाक से मुक्ति- तीन तलाक से सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब मुस्लिम महिला ही होती थी। जिनके पास तीन तलाक के बाद जीवन में केवल अंधेरा ही था। आर्थिक पक्ष देखें तो और नीचे की श्रेणी में पहुंच जाती थीं।

सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद पर काबू पाया गया। शांति स्थापित होने के साथ जम्मू कश्मीर के आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुले। आर्थिक प्रगति की हिस्सेदारी गरीबों को मिली। गरीबों को ऊपर उठने में सहारा मिला।

धारा 370 का उन्मूलन एक देश एक राष्ट्र, एक प्रधान, एक कर व्यवस्था, एक कानून के साथ-साथ जम्मू कश्मीर को देश की आर्थिक प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका मिला। प्रगति में हिस्सेदारी मिली। जब प्रगति में हिस्सेदारी आई तब गरीब को गरीबी की बेड़ियां तोड़ने में समय नहीं लगा। गरीब- गरीबी रेखा से ऊपर आया। अंत्योदय का सिद्धांत सफल सिद्ध हुआ।

रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया, गुलामी का एक निशान और समाप्त हुआ। 92 साल पुरानी प्रथा समाप्त करके रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। संसाधनों के आवंटन व प्रबंधन में मदद मिली। बुनियादी ढांचे में बेहतर भविष्य की आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निवेश आया।

रेलवे और देश के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली। वित्तीय अनुशासन मजबूत हुआ। समग्र परिवहन तंत्र- सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग व रेलवे के बीच समन्वय स्थापित हुआ। सुचारू, सुदृढ़, मजबूत, विकसित व सुरक्षित परिवहन से रेलवे के साथ-साथ देश के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिली। विकास बढ़ा, गरीब को सहारा मिला, अंत्योदय का सिद्धांत सार्थक सिद्ध हुआ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 12 करोड़ किसानों को 6000 रूपये का आर्थिक सहयोग प्रदान कर सहारा दिया गया। उनमें साहस पैदा किया गया। गरीबी से ऊपर उठने में मदद की। कर्ज में दबने से बचाया। फिर अंत्योदय को सफलता मिली। 11,57,20,968 घरों में शौचालय का निर्माण कर माता बहनों के सम्मान की रक्षा की गई। स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान से गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से गरीबों को बचाया गया। गरीबों के समय, धन, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी गई। स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा लाभ गरीबों की आर्थिक उन्नति लाने में हुआ।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6,80,29,906 मुफ्त इलाज गरीबों के किए गए। 6,80,29,906 मुफ्त इलाज की व्यवस्था सरकार ने नहीं की होती तो कितने गरीबों को अपने लोगों को खोना पड़ता। इलाज के लिए घर, दुकान, खेत, जमीन तो सब बिक गए होते। ऋणों के बोझ में और दब जाते। प्रधानमंत्री जी ने सहारा दिया, फ्री इलाज की व्यवस्था कर गरीबों की आर्थिक स्थिति को गिरने से रोका गया। गरीब को और गरीब होने से बचाया। अंत्योदय को सफल सिद्ध किया।

भाजपा सरकार अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की। दोनों ही सरकारों के बजट, आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति, युवा नीति, खेल नीति, कृषि नीति, स्वास्थ्य नीति, उद्योग नीति, व्यापार नीति, रक्षा नीति कोई भी नीति हो, हर नीति का परिणाम गरीब कल्याण, गरीबों की योजनाओं में भागीदारी और भागीदारी से आर्थिक उन्नति।

यह सफलता भारत ही नहीं विश्व में चर्चा का विषय है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 25 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से ऊपर आना कोई छोटी बात नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का दायरा और बढ़ाया। गरीबी रेखा से ऊपर आए लोग फिर से किसी कारण से गरीब वापस ना हों, वापस पीछे ना चले जाऐं, उनको सहारा चालू रखा, अब यह गरीबी रेखा से ऊपर आए लोग और तेज कदम आगे बढ़ाएंगे। आगे से पीछे के लोगों का सहारा बनेंगे। अंत्योदय का सूत्र रामबाण बन गया। धीरे-धीरे गरीबी खत्म होने लगी। जिस गति वा जिस पैमाने पर आर्थिक प्रगति हो रही है इसे देखकर के बड़ी गंभीरता व विश्वास के साथ कहा जा सकता - वह दिन दूर नहीं जब **अंत्योदय से विकसित भारत@2047** की सिद्धि प्राप्त होगी। ▪

(लेखक भाजपा म.प्र. के कोषाध्यक्ष एवं गेल इंडिया के स्वतंत्र डायरेक्टर हैं।)

विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट - प्रधानमंत्री

रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है।

अब इस बजट में सरकार ने Employment Linked Incentive scheme की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे।

केन्द्रिय बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव-गरीब-किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नीयो मीडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानि की लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी।

रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने Employment Linked Incentive scheme की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत, जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह, हमारी सरकार देगी।

स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब नौजवान साथी, बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गाँव, हर घर entrepreneurs बनाना हैं। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।

हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर, मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से MSME सेक्टर की ownership मध्यमवर्गीय है। और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है। मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। E-Commerce Export Hubs और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी।

ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकॉनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड हो, Angel Tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं।

रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकॉनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स देश में नए सैटलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए Transit Plans... इससे देश में नए economic hub विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे।

डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। पूरी दुनिया

में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है। बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है।

NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास...पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे।

इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं।

इससे एक ओर छोटे किसानों को फल-सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे...तो दूसरी ओर, हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल-सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए, दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है।

देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, Saturation Approach के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना, 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को All Weather Roads से जोड़ेगी। इसका लाभ, देश के सभी राज्यों के दूर-दराज गांवों को मिलेगा।

बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये Better Growth और Bright Future लेकर आया है। बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के, उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। ▪

केन्द्रिय बजट का लक्ष्य विकसित भारत

डॉ. मोहन यादव

केन्द्रीय बजट के माध्यम से महंगाई दर पर कन्ट्रोल करने की भावना परिलक्षित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक और महंगाई दर में स्थिरता हासिल की गई है। यह बजट भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है।

- **केन्द्रिय बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है।**
- **नयी टैक्स रिजीम में बदलाव, मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाने तथा युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष पैकेज के निर्णय ऐतिहासिक।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित केन्द्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। बजट में दैदिप्यमान भारत का भाव और महंगाई दर पर नियंत्रण की भावना स्पष्टत: परिलक्षित होती है। कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केन्द्रित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश को भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाने का मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की संभावना निहित है।

केन्द्रीय बजट के माध्यम से महंगाई दर पर कन्ट्रोल करने की भावना परिलक्षित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक और महंगाई दर में स्थिरता हासिल की गई है। यह बजट भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है। नयी टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50 हजार से 75 हजार रुपये, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए करने तथा 30 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह बजट विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति का आधार बन हर भारतीय की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। ▪

जनहितैषी और विकास हितैषी बजट : अमित शाह

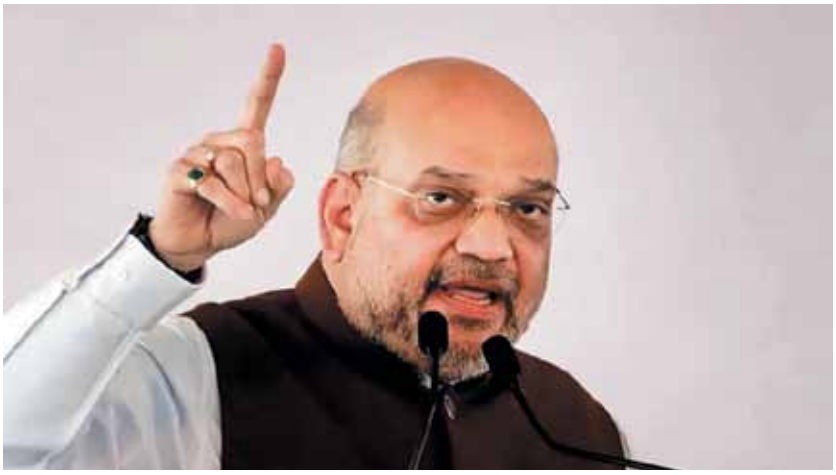

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है।

बजट में 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए Entrepreneurship के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी।

बजट 2024-25 जनहितैषी एवं विकास हितैषी है। इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत-बहुत बधाई।

बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।

यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और Entrepreneurship को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी।

किसान कल्याण हमेशा से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की योजनाओं व नीतियों के केंद्र में रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाली है। साथ ही, इस बजट में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सर्टिफाई करने, 10 हजार बायो-इनपुट सेंटर्स की स्थापना, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, 400 जिलों में खरीफ फसलों का क्रॉप सर्वे और तिलहनों के लिए एक कार्यनीति का निर्माण जैसे निर्णयों से कृषि क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। बजट में 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए NABARD के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी।

हमारे MSME सेक्टर में मोदी जी के विश्वास को प्रतिबिंबित करते हुए, बजट 2024-25 इस क्षेत्र को एक नई ताकत देता है। निर्यात केन्द्रों, ऋण गारंटी, संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण और क्लस्टरों में SIDBI की नई इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, यह क्षेत्र राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता, मध्यम वर्ग के लिए रोजगार और समृद्धि के एक नए युग की पटकथा लिखते हुए भारत को विनिर्माण क्षेत्र की स्थायी मशीन में बदल देगा।

बजट 2024-25 बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। बाढ़ प्रभावित बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को आवश्यक राहत प्रदान करते हुए बजट में प्रभावित क्षेत्रों का कायाकल्प करके और बाढ़ की रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लोगों के सपनों को नया रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देने हेतु इस बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए 'पूर्वोदय' योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, रोजगार व आर्थिक विकास के अवसरों को नई ऊर्जा मिलेगी और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। जनजातीय समाज का उत्थान

व उनका सशक्तीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। बजट में सरकार ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए 'पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान से 63 हजार गाँवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय बहन-भाई लाभान्वित होंगे। इससे न सिर्फ ये गाँव विकास की मुख्यधारा में जुड़ेंगे, बल्कि उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से वे आदर्श ग्राम भी बनेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दस वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास का स्वर्णिम युग देखा है। बजट 2024-25 बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक पहल के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को 11,11,111 करोड़ रुपए का आवंटन और 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से लैस भारत का निर्माण करेगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा।

मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को नई ऊँचाई देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इस बजट में Women-led development को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन इसका प्रतिबिंब है। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों की बाजार तक पहुँच बढ़ाने, मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क कम करने की दिशा में राज्यों को प्रोत्साहन देने जैसे निर्णयों के लिए मोदी जी का आभार।

बजट 2024-25 भारत की आर्थिक वृद्धि को देश की युवा शक्ति के साथ जोड़ने के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसमें 4.10 करोड़ युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशाल कोष उपलब्ध कराया गया है, जबकि शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक और गेम-चेंजिंग कदम की कल्पना की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इन अभूतपूर्व पहल से युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की एक नई दुनिया खुलेगी।

बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर उनके सपनों को नया विस्तार दिया है। टैक्स में छूट हो या उसके नियमों को आसान करना हो, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देना हो या कैंसर के मरीजों को दवाओं में राहत देने का निर्णय हो, यह बजट मध्यम वर्ग के जीवन को और भी आसान बनाने वाला है। केंद्रीय बजट में घोषित रोजगार से जुड़ी अभूतपूर्व पहल औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में योगदान देंगी। भविष्य निधि योजना और नए लोगों को प्रोत्साहन देने वाली पहल से 2.90 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है और यह भारत के औपचारिक क्षेत्र को रोजगार सृजन इंजन में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी ।

पीएम आवास योजना करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। बजट में इस योजना को और विस्तार देते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गयी। साथ ही, औद्योगिक कामगारों के लिए डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा के प्रावधान के निर्णय से गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों व श्रमिकों के जीवन को सहारा मिलने वाला है। देशवासियों के आय से लेकर आवास तक की सुविधा का ध्यान इस कल्याणकारी बजट में लिया गया है।

मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करके भारत की उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित किया गया है। इस निर्णय से न केवल भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, बल्कि छोटे और महिला उद्यमियों को रोजगार सृजनकर्ता बनने की राह पर भी अग्रसर किया जाएगा। ▪

कार्यकर्ता जनता की सेवा करने में सहायता करें : डॉ. मोहन यादव

हम भाग्यशाली हैं कि हमने पांचवीं बार मध्यप्रदेश में सरकार बनाई है। हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में प्रदेश के बजट को दोगुना करना है और इसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। हमारी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं और पार्टी कार्यकर्ता इन योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा करने में सरकार की सहायता करें।

जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अपने के शव को साइकिल पर ले जा रहा है, तो यह देखकर बहुत कष्ट होता है। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से यह प्रबंध कर दिया है कि ऐसी स्थितियां न बनें। इसके लिए एंबुलेंस या शव वाहन की व्यवस्था की गई है।

हमारे कार्यकर्ता भी अपने आसपास निगाह रखें कि यह व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं। कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही? अगर हम सजग रहेंगे, तो ऐसी लापरवाही को रोक सकेंगे। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए खाली पदों पर भर्ती करने जा रही है। जो पद प्रमोशन से भरे जाने थे, उनकी प्रक्रिया में हमारे विरोधियों के रवैये के कारण थोड़ा व्यवधान आया है, जो बार-बार इस मामले को अदालत में ले जाते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हम क्षेत्रीय आधार पर योजना बना रहे हैं। उज्जैन में हुई रीजनल समिट इसका उदाहरण है। दूसरी रीजनल समिट जबलपुर में, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। कृषि सेक्टर के विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार माइनिंग, एविएशन आदि क्षेत्रों में भी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के लिए 55 जिलों में 55 एक्सीलेंस कॉलेज प्रारंभ हो रहे हैं। इन कॉलेजों में हम सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं। कार्यसमिति में बजट में किए गए कुछ प्रावधानों को प्रस्तुत किया है, सभी से आग्रह है कि व्यापारी संगठनों के माध्यम से, प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से इन बातों को संबंधित वर्गों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री जी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में साढ़े 5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। अपने-अपने स्तर पर अपने-अपनी पंचायत तक भी इस एक पेड़ मां के नाम का अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। ▪

विकसित भारत बनाने का बजट :

विष्णुदत्त शर्मा

देश में झूठ, छल-कपट की राजनीति करने वाला विपक्ष सदन में भी नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। विपक्षी नेता कह रहे थे कि बजट में देश के 17 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई अवसर नहीं है।

बीते दस सालों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। मोदी सरकार ने हर समाज, हर वर्ग के लिए काम किया है और वर्तमान बजट भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला तथा अमृतकाल की संकल्पनाओं को सिद्ध करने वाला बजट है।

- **बजट- 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला है।**
- **बजट- सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी है।**
- **बजट में दिखी 'मोदी के मन में एमपी' की झलक।**
- **बजट पर झूठ, छल-कपट की नकारात्मक राजनीति करना चाहता है विपक्ष।**
- **राहुल गांधी टीकमगढ़ की जिस बहन से मिले, उसकी कभी सुध नहीं ली।**

मोदी सरकार का नया बजट देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की पूर्ति करने वाला बजट है। विपक्ष सिर्फ झूठ, छल-कपट की नकारात्मक राजनीति करता है। वास्तव में मोदी सरकार का बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख है।

देश में झूठ, छल-कपट की राजनीति करने वाला विपक्ष सदन में भी नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। विपक्षी नेता कह रहे थे कि बजट में देश के 17 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई अवसर नहीं है। बीते दस सालों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। मोदी सरकार ने हर समाज, हर वर्ग के लिए काम किया है और वर्तमान बजट भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला तथा अमृतकाल की संकल्पनाओं को सिद्ध करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है।

जब हम मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, तब हमने कहा था कि एमपी के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में एमपी। इसी नारे के साथ हमने चुनाव अभियान चलाया और विधानसभा में जीत का रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा चुनाव में तो सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि छिंदवाड़ा इसका गढ़ है, उसका गढ़ है। हमने कहा यह मोदी सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है और छिंदवाड़ा में भी जीत हासिल की। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे भी यह बात झलकती है कि 'एमपी के मन में मोदी'। इस बजट में मध्यप्रदेश को 97907 करोड़ रुपए दिये गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 11205 करोड़ रुपए अधिक हैं। मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं के लिए 14738 करोड़ रुपये दिये गए हैं, कांग्रेस के समय में केवल 632 करोड़ रुपये मिलता था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं के विकास का ऐतिहासिक काम हुआ है। विगत 10 वर्षों में 1062 फ्लाईओवर से लेकर के कई प्रकार की सौगातें मध्यप्रदेश को मिली हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली थी, तब कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश पर राज किया, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम गरीबों के लिए एक रुपया भेजते हैं, तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिये खा जाते हैं। गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार ने सुशासन और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए जो प्रयास किए हैं, उनके परिणामस्वरूप पूरा एक रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गईं, उनके कारण आज भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं।

मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न

योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में 30 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का फ्री का इलाज करने का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ परिवारों को उनके सर पर छत देकर उनके जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, उनके लिए 3 करोड़ आवास और बनाए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक बहनों को गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार ने गांव-गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी।

आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक-एक गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खाते खोलने की बात कही, तो विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन इन खातों की वजह से दलाल और बिचौलियों से मुक्ति मिली है। डीबीटी के कारण देश में 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2008 में बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के टिपारिया गांव में एक बहन भंजन बाई के घर गए थे। वो बता रहे थे कि मैं इससे मिला, उससे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार 2014 तक चली, तब इतने सालों तक बहन भंजन बाई का क्या हुआ, नेता प्रतिपक्ष को पता भी नहीं होगा। आज उस बहन के सर पर छत देने का काम भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।

नेता प्रतिपक्ष बुंदेलखंड की गरीबी और समस्याओं पर अलाप करके आए थे, लेकिन उस बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पिछले बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44605 करोड़ का प्रावधान करके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा करने का काम किया था। बुंदेलखंड अब सूखा नहीं, हरा-भरा होगा। गरीब नहीं, समृद्धशाली होगा। वहां पर्यटन के विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी जी ने बुंदेलखंड की जनता के लिए वंदे भारत समेत रेल सुविधाओं की सौगात दी है। औद्योगीकरण से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में ही नेचुरोपैथी तथा योग केंद्र के विकास का प्रावधान बजट में किया गया है।

2014 के पहले तक देश में 7 एम्स थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब 706 हो गए हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए देश में सीटें 51000 थीं, जो अब 107000 हो गई हैं। 2014 में देश में केवल 17 एयरपोर्ट थे जो 2024 तक बढ़कर 148 हो गए हैं। नए बजट में भी देश की अधोसंरचना के लिए प्रावधान करके मोदी सरकार ने देश के विकास की राह को प्रशस्त किया है।

कांग्रेस की सरकारों द्वारा उपेक्षित कृषि और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए इस बजट में 1.52 लाख करोड़ के प्रावधान किए हैं और सभी प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्य का प्रावधान किया है। किसानों को 1.8 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता देकर प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उत्थान का काम किया है। भारत सबसे युवा राष्ट्र है। देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। 15 से 29 वर्ष तक के युवाओं की संख्या 38 करोड़ है। पहली बार वोट देने वाले 1.85 करोड़ नौजवानों ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीसरी बार चुनकर भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार देश के युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में 8 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं तो 2017 से 2024 के बीच 6 करोड़ 20 लाख युवा सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं। युवाओं के लिए इस बजट में 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों से अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ▪

कार्यकर्ताओं की मेहनत से संकल्प की पूर्ति: विष्णुदत्त शर्मा

विधानसभा के चुनाव के पूर्व ग्वालियर में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हमारे नेता श्री अमित शाह ने संकल्प दिलाया था कि मध्यप्रदेश में सिर्फ सरकार नहीं बनेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस संकल्प की पूर्ति हुई। 2023 के चुनाव में हमने 49 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया और 163 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हमने नारा दिया था-'मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी', जिसे प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भरपूर आशीर्वाद देकर साकार कर दिया। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में खुशियां ला रही हैं, तो दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार गुड गवर्नेंस को साकार कर रही है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के हितग्राही भारतीय जनता पार्टी की ताकत रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जीत का श्रेय इन्ही कार्यकर्ताओं को जाता है। 41 लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए बूथ विजय के लिए मैदान में उतरे और झूठ, छल-कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंका। बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ही हम 59.27 प्रतिशत वोट हासिल करने में सफल रहे और 80.56 प्रतिशत बूथों पर हमने जीत हासिल की। अन्य वर्गों के साथ अजा और अजजा वर्ग में भी भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है। आने वाले समय में हमें उन क्षेत्रों में अपना वोट शेयर बढ़ाने के प्रयास करना है, जहां अभी हमें कम वोट मिले हैं। ▪

प्रदेश का बजट - सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

"विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश" की थीम पर प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए आगामी पाँच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। बजट में सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है।

प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, अपितु सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है।

''विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश'' की थीम पर प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए आगामी पाँच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। बजट में सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है। आईटी सहित नवीन तकनीक के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासनिक सेवाओं में प्रदेश के युवा अधिक से अधिक संख्या में आए, इस उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में उनका योगदान बढ़ाने के लिए दीर्घगामी योजना पर कार्य होगा।

जो विद्यार्थी छात्रावासों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए बजट में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की गई है। गौ-शालाओं के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधान में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भारी उद्योग, एमएसएमई और कुटीर उद्योग सहित स्व-सहायता समूह के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, एक्सप्रेस-वे पर विशेष ध्यान होगा। महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा, आदि की सीधी कनेक्टिविटी राजधानी से जुड़े, इस उद्देश्य से पर्याप्त व्यवस्था करते हुए वित्तीय तरलता का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सिंहस्थ का वृहद स्तर पर आयोजन होने वाला है। उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और दिव्य होता है। सिंहस्थ के लिए इंदौर एवं उज्जैन संभाग के 13 जिलों के देव-स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था के उद्देश्य से टोकन राशि के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक प्रदेश की थाती हैं, उनके लिए विशेष योजना आरंभ की जा रही है। अन्य प्रदेशों या विदेशों में कार्यरत युवाओं के माता-पिता की देखरेख के लिए नगरीय क्षेत्र में ऐसी सोसायटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा सहित सभी आवश्यक व्यवस्था हो। इस दिशा में आगे आने वाले प्रायवेट सेक्टर को राज्य शासन की ओर से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश में रिकार्ड संख्या में पर्यटक पधारे हैं। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ हैरिटेज टूरिज्म, वन पर्यटन में पर्याप्त गतिविधियां हैं। इसके साथ-साथ एजुकेशन व हेल्थ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में ''श्रीअन्न'' उत्पादन क्षमता देश में सर्वाधिक है। इसे प्रोत्साहन देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। डिण्डौरी में ''श्रीअन्न अनुसंधान केन्द्र'' खोला जा रहा है।

इसी प्रकार दलहन अंतर्गत चना अनुसंधान केन्द्र मालवा में, सरसों अनुसंधान केन्द्र चंबल में खोला जाएगा। गौ-वंश संबंधी अपराधों को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए कठोर कार्रवाई के साथ-साथ गौ-वंश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन ने इस वर्ष को गौ-वंश रक्षा वर्ष घोषित किया है। राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप दो करोड़ 30 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। प्रदेश में रोजगारपरक योजनाओं को लागू करते हुए सामान्यजन के बेहतर जीवन के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत रहेगी। ▪

मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा व ऐतिहासिक बजट- विष्णुदत्त शर्मा

- **3 लाख 65 हजार करोड़ का मध्यप्रदेश सरकार का बजट।**
- **सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के भाव को पूरा करेगा बजट।**
- **भाजपा की मोहन सरकार का यह बजट कुशल प्रबंधन की मिसाल है।**
- **प्रदेश को विकसित बनाएगा, हर वर्ग के जीवन में खुशियां लाएगा नया बजट।**

3 लाख, 65 हजार, 67 करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन की मिसाल है। भाजपा सरकार का फोकस हमेशा से विकास पर रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय बजट प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला है, जिसमें गरीब कल्याण का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ धोखा किया है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं से जो वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। वहीं भाजपा की सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर हाथ को काम की अवधारणा पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं, व प्रदेश की जनता से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगार का जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ सी.एम. राईज योजना शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सी.एम. राईज विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। सी.एम. राईज विद्यालयों के लिये रूपये 2 हजार 737 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 14 तक पहुंचा दिया है। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय-मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में शुरू हो जायेंगे। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 46 हजार पदों का सृजन किया है। 2003 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। न तो बिजली आती थी और न ही सड़कें थीं। आज भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आ गया है। बीते सालों में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो प्रयास किए, उनके फलस्वरूप बीते 20 सालों में प्रति व्यक्ति आय 11 गुना बढ़कर 1.42 लाख रूपये प्रति वर्ष से ऊपर पहुंच गई है तथा बीते 10 सालों में प्रदेश के 2.30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए है।

भाजपा सरकार द्वारा बीते सालों में बेटियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनका प्रतिफल प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के रूप में सामने आया है। मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजनाओं की चर्चा देश भर में हो रही है। वर्तमान में लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 48 लाख 3 हजार बालिकाओं को मिल रहा है। शिशुओं की बेहतरी के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 11 हजार 706 केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र में उन्नत किया जा रहा है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 26 हजार 560 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है।

एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग कांग्रेस के लिए वोट बैंक रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इन वर्गों की बेहतरी के लिए जमीन पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों का अपमान किया जबकि भाजपा ने मुख्यधारा से जोड़ा। भाजपा की सरकार जहां

एक तरफ इन वर्गों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इन वर्गों के युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें । जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 94 सी.एम. राईज विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों के परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रूपये 450 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सागर में संत रविदास स्मारक का निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक बनेंगे। कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश ने ऊर्जा के अकाल का दौर भी देखा है। भाजपा सरकार द्वारा बीते 20 सालों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आज मध्यप्रदेश न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली दे रहा है। प्रदेश में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सहित ताप विद्युत संयंत्रों से भी ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है। बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके पूरे होने पर सूखे कहे जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों के 1 हजार 900 ग्रामों में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ-साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। ▪

संकल्पों को सिद्ध करने के लिए चुना है : पीएम मोदी

भारत की आजादी के इतिहास में, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में, बहुत दशकों बाद देश की जनता ने, एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। 60 साल के बाद ये हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फिर से, उसकी वापसी हुई है।

भारत के लोकतंत्र की छह दशक के बाद आई हुई ये घटना असामान्य घटना है।

दस वर्षों के लिए अखंड, एकनिष्ठ, अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिया है,आशीर्वाद दिए हैं। इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने propaganda को परास्त कर दिया है। performance को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मुहर लगा दी है।

संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं।

मेरे जैसे बहुत लोग हैं, इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच या गांव का प्रधान भी नहीं रहा है। राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है। लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर के देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उससे हम जैसे लोगों को अवसर मिले हैं। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है। और जनता जनार्दन ने उस पर मुहर लगाई है, तीसरी बार आने का मौका मिल गया।

संविधान हमारे लिए ये कोई articles का compilation मात्र नहीं है। हमारे लिए उसका spirit भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान हैं। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार की नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाईट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, मार्गदर्शन करता है।

जब लोकसभा में सरकार की तरफ से कहा गया कि 29 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनायेंगे। तो मैं हैरान हूं, जो आज संविधान

आजादी के इतिहास में, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में, बहुत दशकों बाद देश की जनता ने, एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। 60 साल के बाद ये हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फिर से, उसकी वापसी हुई है।

की प्रति लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था, 26 जनवरी तो है तो ये संविधान दिवस क्यों लाए और संविधान दिवस के माध्यम से देश के school, colleges में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरूषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों को स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में school, colleges में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हों, चर्चा सभाएं हों, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो, देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड, संविधान, हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे । जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया है। और इससे देश के कोने-कोने में संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है, उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है।

देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है। वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि-कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए हैं।

ये चुनाव दस वर्ष की सिद्धियों पर तो मुहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना है। क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने

के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया है।

देश भलीभाँति जानता है, देश ने पिछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दस नंबर से पांच नंबर पर पहुंचाने में सफलता पाई है। और जैसे-जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है, एक की तरफ पहुंचता है तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं। और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद, संघर्षों की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दस नंबर से विश्व में पांच नंबर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं। इस बार देश की जनता ने हमें पांच नंबर से तीन नंबर की इकोनॉमी तक पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप-3 में पहुंचाकर रहेंगे।

आने वाले वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है, उसकी गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प हैं उसके हिसाब से तो ये appetizer है, main course तो अभी शुरू हुआ है।

आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के हैं। और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं।

आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं, आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष हैं और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा।

जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है।

हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप्स का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं।

आने वाले कालखंड में हमारे टीयर-2, टीयर-3 cities भी growth engine की भूमिका में देश में बहुत बड़ा contribution करने वाले हैं।

ये शताब्दी technology driven शताब्दी है और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए footprints भी अवश्य रूप से देखेंगे।

आने वाले 5 साल में public transport में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के कोटि-कोटि जनों को जल्द से जल्द मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं।

भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे innovation हो, चाहे patent की रजिस्ट्री हो, हमारे छोटे-छोटे शहर, हजारों की तादाद में ऐसे शहर भारत में विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं।

भारत की विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ, उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं।

हमारे देश के किसान, गरीब, युवा और नारीशक्ति, हमारी विकास यात्रा में, हमारा जो फोकस है, उसको हमने रेखांकित किया है।

बीते 10 वर्ष में खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, उस पर ध्यान केंद्रित किया है और अनेक योजनाओं से उसको ताकत देने का प्रयास किया है। चाहे फसल के लिए ऋण हो, लगातार नए बीज किसानों को उपलब्ध हो। आज की कीमत उचित हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी मुसीबतें दूर करके किसानों को सरलता से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की है। चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर के किसानों को लाभ पहुंचाया है। एक प्रकार से बीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए हर व्यवस्था को बहुत micro-planning के साथ मजबूती देने का भरपूर-भरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को चाक-चौबंद किया है।

पहले छोटे किसानों को- किसान क्रेडिट कॉर्ड, लोन पाना करीब-करीब ना के बराबर था, बहुत मुश्किल था। जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक थी, आज हमारी नीतियों के कारण, किसान क्रेडिट कॉर्ड के विस्तार के कारण। हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा हैं और व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कॉर्ड, पशुपालकों को और मछुआरों को किसान क्रेडिट कॉर्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। और इसके कारण हमारे किसानों का खेती के काम को उसके विस्तार को भी मजबूती मिली है, उस दिशा में भी हमने काम किया हैं।

कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में, एक बार किसानों की कर्ज माफी के बहुत ढोल पीटे गए थे। और बढ़-चढ़कर के, बातें बताकर के किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया था, और 60 हजार करोड़ की कर्जमाफी, उसका इतना हल्ला मचाया था। और एक अनुमान था कि उसके लाभार्थी सिर्फ देश के तीन करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान को तो उसमें नामो-निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी, और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था।

जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय के केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती हैं, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है उसका उदाहरण देना चाहता हूं।

हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ 10 करोड़ किसानों को हुआ है। पिछले 6 सालों में हम 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुके हैं।

झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। इनका सत्य से मुकाबला करना इसके लिए जिनके हौसले नहीं हैं वो बैठकर के इतनी चर्चा के बाद उन्हें उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है।

वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुईं कि fertiliser के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब-करीब 12 लाख करोड़ रुपये fertiliser में सब्सिडी दी है और जो भारत की आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और इसी का परिणाम है कि हमारे किसान को fertiliser का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया, सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया।

हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी की है। इतना ही नहीं खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी। लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर-करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया है।

10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक ढाई गुना अधिक पैसा पहुंचाया है और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का incremental वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते, हम नए-नए क्षेत्रों को उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए अन्न

भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ लिया है और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है, हम चाहते हैं किसान उस तरफ बढ़े और उसके भंडारण के लिए भी एक व्यापक infrastructure की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की। हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। हमारे दिव्यांग भाई-बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ कर के माइक्रो लेवल पर उसको address करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है।

हमारे समाज में किसी न किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग यानी एक प्रकार से समाज में बार-बार हर दूत (प्रताड़ित) होने वाला वर्ग वो transgender वर्ग है, हमारी सरकार ने transgender साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पश्चिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता है कि भारत इतना progressive है। भारत की तरफ बड़े गर्व की नजरों से देखा जाता है। हमने उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा पद्म अवार्ड में भी transgender को अवसर देने में हमारी सरकार आगे आई है।

हमारे घूमंत जनजातीय समुदाय, घूमंत साथी, बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम address कर सकें और उनको भी एक स्थायी, सुरक्षित और संभावनाओं वाला जीवन प्राप्त हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं, PVTG, हमारे जनजातीय समूह में ये सबसे पीछे रहा हुआ और आजादी के इतने सालों बाद भी जिन्होंने उनको निकट से देखा होगा उनको पता चलता है कि ये कैसी हालत में जीते हैं, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत 34 हजार करोड़ रुपए, ये समुदाय बिखरा हुआ है। छोटी संख्या में है, वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपरा है कि जिसकी वोट ताकत है उसी की चिंता करना, लेकिन समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था, हमने उसकी चिंता की है क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं विकास की राजनीति करते हैं।

हमारे देश में पारंपरिक पारिवारिक कौशल्य भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है। जो विश्वकर्मा समूह है, जिनके पास परंपरागत हुनर है वो जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी करता है लेकिन उनको कभी address नहीं किया गया। हमने करीब-करीब 13 हजार करोड़ की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना, उनके अंदर professionalism आये।

गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था, लेकिन रेहड़ी-पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी, ये हालत थी। पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों की चिंता की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से बाहर आ करके अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी-पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं। वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं और जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी बैठता था आज एक छोटी दुकान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो पहले खुद मजदूरी करता था आज एकाध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है और यही कारण है कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है।

हम women led development की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी women development तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं। लेकिन women led development की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ women led development की ओर कदम बढ़ाए हैं और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है। हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो contribute कर रहा है।

Women health, sanitation, wellness पर हमने दस वर्षों में एक priority sector के नाते काम किया है।

टॉयलेट हो, सैनेटरी पेड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेग्नेंसी के दौरान vaccination की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारी देश की माताओं-बहनों को मिला है।

आरोग्य के साथ-साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर दिए हैं। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी हैं।

Women self help groups उससे जुड़ी दस करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक एक करोड़ बहनें जो इस self help groups में काम करती हैं। छोटा-छोटा गांव में कारोबार करती हैं, मिलकर के करती हैं। किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन्हीं में से एक करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं। और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं।

सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, वो अगुवाई करें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई technology आती है लेकिन महिलाओं के नसीब में बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई technology का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको लीड करें और इसी के तहत नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और आज गांव में किसानों की मदद करने का technology के माध्यम से, गांव की हमारी महिलाएं कर रही हैं और मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे कह रही हैं हम लोग तो कभी साईकिल भी नहीं चलाना जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गांव हमें पायलट दीदी के नाम से जानने लगा है। और ये गरिमापूर्ण बात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा driving force बन जाता है।

देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो selective रवैया है। ये selective रवैया बहुत ही चिंताजनक है।

मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है, वो बहन चीख रही है लेकिन वहां खड़े हुए लोगों में से कोई उसकी

मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेशखलि में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं।

भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनकर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्वस्त किया है। और इस नतीजों के कारण भारत विश्वभर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनकर के उभर रहा है। If's और But's का समय पूरा हो चुका है। और भारत में विदेश का निवेश भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आता है। भारत के युवाओं के टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक अवसर बन जाता है।

विश्व पारदर्शिता पर भरोसा करता है। और भारत उसके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ भूमि के रूप में उभर रहा है।

इस चुनाव नतीजों से जो capital market है, उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है। लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है।

इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है कि हां अगर संविधान की रक्षा को कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है।

आपातकाल को मैंनें बहुत निकट से देखा है करोड़ों लोगों को कठिन यातनाएं दी गई हैं, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों के ऊपर जुल्म करते रहें और आप संविधान हमें सिखाते हो।

दर्जनों articles पर यानि संविधान की आत्मा को छिन्न-विछिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां, और 42वां संविधान संशोधन और उस संशोधन में यानि mini-constitution के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर-कर के आप बैठे हुए लोग हो। इमरजेंसी में पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में थे खड़गे जी, क्या हुआ था। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर NAC बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था, किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने। आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था। और remote-pilot बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है।

जरा ये बताए हमको वो कौन-सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है, वो कौन-सा संविधान था, किस हैसियत से फाड़ा गया था।

हमारे देश में लिखित रूप में protocol की व्यवस्था है राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर सब कैसे-कहां होते हैं। कोई मुझे बताए कि संविधान की मर्यादाओं को तार-तार करके protocol में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी, कौन-सा संविधान था। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग बाद में, एक परिवार के लोग पहले, कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने। और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो India is Indira, Indira is India नारे लगाकर के जीये हो, आप संविधान की कोई आदर-भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो।

देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, उसके जहन में है।

आपातकाल सिर्फ एक राजनैतिक संकट नहीं था। लोकतंत्र, संविधान के साथ-साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जय प्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई की बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए, ये हाल इन्होंने कर दिया था। और प्रताड़ना सिर्फ राजनेताओं की नहीं, आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया था, सामान्य मानवी को भी नहीं। और इनके इतने सारे जुल्म, उसमें इनके लोग भी थे अंदर, उसके साथ भी जुल्म हुआ।

वो दिन ऐसे थे कि जो कुछ लोग घर से निकले कभी घर लौट करके वापस नहीं आए और पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कहाँ गया, यहां तक की घटनाएं घटी थीं।

बहुत सी पार्टियां जो अल्पसंख्यकों की आवाज होने का दावा करती हैं और बड़ी ज्यादा चिल्ला करके बोलते हैं। क्या कोई मुजफ्फरनगर और तुर्क मान गेट वहां अल्पसंख्यकों के साथ इमरजेंसी में क्या हुआ था जरा याद करने की हिम्मत करते हैं क्या, बोलने की हिम्मत करते हैं क्या?

उस समय कई अलग छोटे-छोटे राजनैतिक दल थे, ये इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरे थे और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जमीन बनाई थी। आज वो कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं।

अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है, ये परजीवी कांग्रेस है। जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी इनको स्वीकार नहीं किया है, वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है। किसी और के कारण सहयोगी दलों के वोट खाकर के वो जरा फली-फूली है। और कांग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है। वे देश की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, वो जोड़ तोड़कर के बचने का रास्ता खोज रहे हैं। जनता-जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए fake narrative के द्वारा, fake video के द्वारा देश को भ्रमित करके, गुमराह करके अपने कारनामें करने की आदत है।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाव आंदोलन चलाने लग गए हैं, बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली हैं भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में इनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं कि आप लोगों को जेल क्यों भेज रहे हो।

भ्रष्टाचार करे AAP, शराब घोटाला करे AAP, बच्चों के क्लास को बनाने में घोटाला करे AAP, पानी तक में घोटाला करे AAP, AAP की शिकायत करे कांग्रेस, AAP को कोर्ट में घसीटकर के ले जाए कांग्रेस और अब कार्यवाही हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं ये लोग। और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगों, कांग्रेस पार्टी से, मैं AAP वालों से कहता हूं। कांग्रेस भी बताए कि आपने प्रेस कांफ्रेंस करके AAP के घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे, कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताए कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कांफ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी क्यों वो सबूत सच्चे थे कि झूठे थे। दोनों एक दूसरे को खोलकर के रख देंगे।

ये ऐसे लोग हैं जिनका दोहरा रवैया है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठकर के जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं। और केरल में उनके शहजादे उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री

जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली ED, CBI की कार्यवाही उस पर हाय-तौबा करते हैं और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं शहजादे। तब लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इसमें भी दोगलापन है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा, यही AAP पार्टी वाले चीख-चीख करके कहते थे कि ED, CBI को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे और ED ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे। उनको तब ED बहुत प्यारा लगता है।

2013 का बयान क्या है, कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस, सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का, कांग्रेस एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग करती है ये मुलायम सिंह जी ने कहा था और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी क्या नेता जी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेता जी तो सच बोलते थे।

मैं रामगोपाल जी को भी ये कहना चाहता हूं कि जरा भतीजे को भी बताएं क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा।

बयान साल 2013 का है। The Congress had used the CBI to strike political bargains in many parties. ये कौन कहते हैं, उनके Comrade श्रीमान प्रकाश करात जी ने ये कहा हुआ है 2013 में कहा, ये एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था। एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वो स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था इसके जीते-जागते सबूत आज मौजूद हैं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार-जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार-जीत के लिए भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा conviction है और मैं मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवीय के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी-जान से जुटा हुआ हूं और मैं इसे पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनीं तब हमने दो बड़ी बातें कहीं थी, एक हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और दूसरा भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था। इसी ध्येय को लेकर के एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्याण योजना हम चला रहे हैं। गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध नए कानून, नई व्यवस्थाएं, नए तंत्र हम विकसित कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 उसमें संशोधन किया है। हमने काले धन के खिलाफ एक नया कानून बनाया, बेनामी संपत्ति को लेकर हम नया कानून लेकर के आए हैं। इन कानूनों से भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो गई है। लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारात्मक रूप से गवर्मेंट में भी बदलाव लाया है। हमने direct benefit transfer पर बल दिया है। हमने digital technology का भरपूर उपयोग किया है। और तभी आज हर लाभार्थी तक उसके हक का फायदा तुरंत सीधा पहुंच रहा है। एक नए पैसे का लीकेज नहीं होता है। ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहलु है। और जब सामान्य नागरिक को ये व्यवस्थाएँ मिलती हैं तब उसका लोकतंत्र में भरोसा बढ़ता है। उसको सरकार में अपनापन महसूस होता है और जब अपनापन महसूस होता है ना तब तीसरी बार बैठने का मौका मिलता है।

मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट देकर रखी है, सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे ये मेरी सूचना है।

कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बचकर के नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है।

राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है।

जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़ें हैं, वो पिछले चार दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबाकर आया इतना नहीं है। भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। ये बहुत बड़ी success है ।

बीते अनेक दशकों में बंद, हड़ताल, आतंकी धमकियां, इधर-उधर बम धमाकों की कोशिशें एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थी। आज इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर पर है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते दस वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एकाध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है। और इस लड़ाई में जम्मू-कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है।

आज जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़कर रखा था। क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब-किताब होता है। नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं। क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है। कभी कोई परवाह ही नहीं की। उसे उसके नसीब पर छोड़ दिया था। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेन, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी। उसमे से initiative बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये हमें स्वीकार करना होगा।

हमने नॉर्थ ईस्ट में गत पांच वर्ष में जो काम किया है और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से शायद उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम पांच साल में किया है इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसका विकास का मूलभूत आधार है। उसको हमने प्राथमिकता दी है और आज भूतकाल के सारे infrastructure से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है।

नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए दस वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए हैं, बिना रूके, बिना थके हरेक को विश्वास में लेते हुए प्रयास किए गए हैं। और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म

देता रहा है। और आजादी से अब तक ये निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठाकर के सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं एक के बाद एक accord करते करते जा रहे हैं। Recorded है सहमति के रिकार्ड हैं और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं रेखा यहां बनानी है, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं।

ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड की लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर counter group को चुनौती देते थे, खून-खराबा होता रहता था। आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं। जो गंभीर गुनाहों के under हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि अदालत को face करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्यायतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्मेंट की रचना पर भरोसा करना ये इसमे से अनुभव होता है और आज हो रहा है।

मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी। 11 हजार से ज्यादा एफआईआर की गई। मणिपुर छोटा सा राज्य है। 11 हजार एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग arrest हुए हैं।

इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। इसका मतलब शांति की आशा रखना, शांति पर भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुल रहे हैं।

मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं। और बच्चों ने अपनी विकास यात्रा जारी रखी है।

केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द का रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे-छोटे इकाइयों, हिस्सों को जोड़कर के इन ताने-बाने को गूथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है, गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार-बार जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे।

Political leadership तो है ही लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका-जिसका इन काम से संबंध है वे लगातार वहां physical जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है।

प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं।

ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रधानमंत्री, प्रधानसेवक के रूप में यहां आया उसके पहले लंबे अरसे तक मुझे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था और इसके कारण मैं अनुभव से सीखा हूं कि federalism का महात्म्य क्या होता है और उसी में से cooperative federalism और उसी में से competitive cooperative federalism इन विचारों को मैं बल देता आया हूं। और इसीलिए जब जी-20 समिट हुई तो हम दिल्ली में कर सकते थे, हम दिल्ली में बहुत बड़ा तामझाम के साथ मोदी की वाह-वाही कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कोने में जी-20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए, उस राज्य को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक प्रतिष्ठा मिले इसके लिए प्रयास किया गया। उस राज्य की branding हो, विश्व उस राज्य को जाने-पहचाने उसके सामर्थ्य को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुद भी अपना नसीब आजमाए इस दिशा में हमने काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि federalism के और रूप होते हैं। जब कोविड के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते थे, जितनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ है शायद हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ है, हमने किया है।

आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए semiconductors और electronic manufacturing जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राथमिकता के साथ अपनी नीतियां बनानी चाहिए, योजनाओं को लेकर आगे आना चाहिए। राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो। निवेश आकर्षित करने वाली नीतियों में स्पर्धा हो और वो भी Good governance के माध्यम से हो, स्पष्ट नीतियों के माध्यम से हो। आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब हर राज्य के लिए अवसर है।

रोजगार सृजन में राज्यों में भी स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे राज्य की उस नीति के कारण उस राज्य के नौजवानों को इतना रोजगार मिला तो दूसरा राज्य कहेगा तुम्हारी नीति में मैंने+1 कर दिया तो मुझे ये फायदा मिला। रोजगार के लिए राज्यों के बीच में स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए। ये देश के नौजवानों के भाग्य को बदलने में बहुत काम आएगा।

आज नॉर्थ असम में सेमीकंडक्टर पर तेज गति से काम चल रहा है। आज इससे असम, नॉर्थ ईस्ट, वहां के नौजवानों को बहुत ही फायदा होने वाला है और साथ-साथ देश को भी फायदा होने वाला है।

यूएन ने 2023 को year of millets के रूप में घोषित किया था। ये भारत की खुद की अपनी ताकत है millets. हमारे छोटे किसानों की ताकत है। और जहां कम पानी है, जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर millets जो कि एक सुपर फूड हैं, मैं मानता हूं कि राज्य इसके लिए आगे आए।

अपने-अपने राज्य के सुपर फूड को millets को ले करके वैश्विक बाजार में जाने की योजना बनाएं। उसके कारण दुनिया के हर टेबल पर हिन्दुस्तान का millets होगा, डाइनिंग टेबल पर और हिन्दुस्तान के किसान के घर में दुनिया से कमाने का अवसर पैदा हो जाएगा। भारत के किसान के लिए समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं।

दुनिया के लिए न्यूट्रेशन मार्केट, इसका सॉल्यूशन भी हमारे देश के millet में है। ये सुपर फूड है। और जहां पर न्यूट्रेशन की चिंता है, वहां पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमें आरोग्य की दृष्टि से भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्य आगे आएं, अपनी पहचान बनाएं।

21वीं सदी में ease of living ये सामान्य मानवी का हक है। और मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें अपनी यहां की नीति, नियम, व्यवस्थाएं, उस प्रकार से विकसित करें ताकि सामान्य नागरिक को ease of living का अवसर मिले ।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसको हमें कई स्तरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा। और इसलिए चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील पंचायत हो, जिला परिषद हो, ये सारी इकाइयों में एक ही मिशन के साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति का राज्य अगर बीड़ा उठाएंगे तो हम बहुत तेजी से देश के सामान्य मानवी को जो भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है, उससे मुक्ति दिला सकेंगे।

समय की मांग है कि हमारे यहां efficiency अब होती है, चलती है का जमाना चला गया है। 21वीं सदी के भारत को अगर भारत की सदी के रूप में अपने-आपको साबित करना है तो हमारे गवर्नेंस के मॉडल में हमारे डिलीवरी के मॉडल में, हमारी निर्णय प्रक्रिया के मॉडल में efficiency बहुत अनिवार्य है। सर्विस की स्पीड बढ़ाने में, निर्णयों की स्पीड बढ़ाने में efficiency की दिशा में काम होगा। और जब इस प्रकार से काम होते हैं तो transparency

भी आती है, if's एंड but's भी नहीं रहते हैं और सामान्य मानवी के हकों की रक्षा भी होती है। और ease of living, इसका एहसास हर नागरिक कर सकता है।

हमारे देश के नागरिकों के जीवन से सरकार की दखल जितनी कम हो, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हां जिनको सरकार की जरूरत है, जिनके जीवन में सरकार की उपयोगिता, आवश्यकता है, उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपने बलबूते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं सरकार का प्रभाव उन्हें रोकने का प्रयास न करें। और इसलिए सरकार की दखल जितनी कम हो, वैसी समाज और सरकार की व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि अब आगे आइए।

क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है। और वो किसी को एक कोने में करने वाला काम नहीं होता है, हमें सामूहिक रूप में मिल करके काम करना होगा। राज्यों को अपना सामर्थ्य बढ़ाना होगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं को हम झेल सकें। पीने के पानी की व्यवस्था, वो भी उतना ही महत्व देना होगा। सामान्य मानवी के आरोग्य की सेवा उसे भी उतना ही महत्व देना होगा।

ये दशक और ये सदी भारत की सदी है। लेकिन भूतकाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आए थे। लेकिन हम अपने ही कारणों से अपने अवसरों को खो चुके थे। अब हमें अवसर खोने की गलती नहीं करनी है। हमें अवसरों को ढूंढना है, हमें अवसरों को जकड़ना है और अवसरों के सहारे हमें अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। उस दिशा में जाने का इससे बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है, जो समय आज भारत के पास है, 140 करोड़ देशवासियों के पास है, विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देश के पास है। और इस वक्त जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वो हमसे आगे निकल चुके हैं, बहुत तेजी से आगे निकल चुके हैं, हम नहीं पहुंच पाए। हमें इस स्थिति को बदलना है। और इस संकल्प को ले करके हमें आगे जाना है। जिन देशों ने 80 के दशक में reforms किए वे आज बहुत तेजी से एक विकसित देश के रूप में खड़े हो गए। हमें reforms पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है, reform से कतराने की जरूरत नहीं है, और reform करते हैं तो खुद की सत्ता चली जाएगी, ऐसे भयभीत रहने की जरूरत नहीं है, सत्ता को हथियाए रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी भागीदारी बढ़ेगी, जितनी निर्णय की शक्ति सामान्य मानवी के हाथ जाएगी, मैं समझता हूं हम भी। भले ही हम शायद लेट हुए हों, लेकिन हम उस आकांक्षा को पूर्ण करने को उस गति को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं।

विकसित भारत का मिशन, ये किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का है। किसी एक सरकार का मिशन नहीं है। देश की सभी सरकारी इकाइयों का मिशन है। और हम एक सूत्र में एक संकल्प के साथ मिल करके चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार कर पाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।

मैं विश्व मंच पर जाता हूं, विश्व के अनेक लोगों से मिलता रहता हूं। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि पूरा विश्व निवेश के लिए तैयार है और भारत उनकी पहली पसंद है। हमारे राज्यों में निवेश आने वाले हैं। उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है। अगर राज्य जितना ज्यादा इस अवसर को जुटाएंगे, उस राज्य का भी विकास होगा। ▪

नई शिक्षा नीति- क्वालिटी आउट ऑफ बॉक्स : अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व में हर क्षेत्र में अव्वल रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा की नींव मजबूत होना आवश्यक है। इसी दिशा में वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति का आगाज किया गया।

इसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ऑर्थोडॉक्स के बदले आउट ऑफ बॉक्स को सार मानते हुए नीति निर्माण किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व में हर क्षेत्र में अव्वल रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा की नींव मजबूत होना आवश्यक है। इसी दिशा में वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति का आगाज किया गया। इसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ऑर्थोडॉक्स के बदले आउट ऑफ बॉक्स को सार मानते हुए नीति निर्माण किया गया। ये गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश में इस नीति को देश में सबसे पहले लागू किया। यह भविष्य के 25 सालों में देश के विद्यार्थियों को विश्व के विद्यार्थियों से स्पर्धा योग्य बनाएगी। यह भी गर्व करने की बात है कि मध्यप्रदेश ने इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा को अपनी मातृ भाषा में पठन-पाठन का अवसर यहाँ के विद्यार्थियों को मुहैया कराया है। उद्देश्य सभी वर्ग के लोगो को प्लेटफार्म देखकर समान अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के सुप्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में देश में मध्यप्रदेश का नाम रोशन करने में समर्थ होंगे। इन एक्सीलेंस कालेजों की विशेषता यह है कि इनमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप सभी कोर्स उपलब्ध होंगे और ये कालेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इनसे युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा। ▪

"एक पेड़ माँ के नाम"अब पूरे देश में जनआंदोलन - अमित शाह

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर प्रारंभ ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जनआंदोलन बन गया है। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव का प्रकटीकरण हैं। पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। मध्यप्रदेश का इंदौर पहले से स्वच्छता, स्वाद, सहयोग, सुशासन और सहभागिता के लिए जाना जाता हैं। अब इंदौर एक पेड़ माँ के नाम अभियान में वृहद पौधा-रोपण के लिए भी देश भर में जाना जाएगा। इंदौर मे 24 घंटे में 11 लाख पौधे रोपने का यह विश्व विक्रम पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। पौधा-रोपण करना सरल है, लेकिन उन्हें बड़ा करना कठिन। पौधों का अपने बेटे की तरह पालन करें। यही वृक्ष आगे एक माँ की तरह आपकी चिंता करेगा। 51 लाख पौधे लगाना और एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाना अपने आप में अभूतपूर्व हैं।

इंदौर स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, क्लीन सिटी, मॉडर्न एजुकेशन का हब बनने के बाद अब ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। जन

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जनआंदोलन बन गया है। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव का प्रकटीकरण हैं। पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है।

मध्यप्रदेश का इंदौर पहले से स्वच्छता, स्वाद, सहयोग, सुशासन और सहभागिता के लिए जाना जाता हैं। अब इंदौर एक पेड़ माँ के नाम अभियान में वृहद पौधा-रोपण के लिए भी देश भर में जाना जाएगा।

सहभागिता से ही किसी भी अभियान को सफल बनाया जा सकता है, जो इंदौर ने पुनः कर दिखाया है। इंदौर में पीपल, बरगद, नीम आदि लंबी आयु के पौधों के रोपण के साथ अमरूद, करोंद, सीताफल, आंवला जैसे औषधीय गुणों वाले पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। साथ ही रेवती रेंज परिसर में तीन तालाब बनाकर उनकी सिंचाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है।

सीआरपीएफ के जवानों द्वारा कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से लेकर गुजरात तक विगत वर्ष 5 करोड़ 21 लाख पौधे लगाने का सराहनीय काम किया है। इसी प्रकार 2024 तक एक करोड़ पौधे और लगाकर 6 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया जाएगा। हमारे शास्त्र और पुराण हमें वृक्ष के महत्व बताते हैं। मत्स्यपुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता हैं। इस प्रकार वृक्ष लगाने के पुण्य को समझाने का काम किया हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि पीछे मुड़कर आने वाली पीढ़ी को देखें। पर्यावरण संरक्षण आज पूरी दुनिया के लिए चिंता बना

पुनः चमकेगा दिनकर

अटल बिहारी वाजपेयी

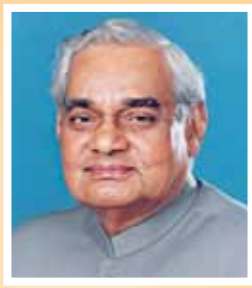

आजादी का दिन मना,
नई गुलामी बीच;
सूखी धरती, सूना अंबर,
मन-आँगन में कीच;
मन-आँगन में कीच;
कमल सारे मुरझाए;
एक-एक कर बुझे दीप,
अँधियारे छाए;
कह कैदी कविराय
न अपना छोटा जी कर;
चीर निशा का वक्ष
पुनः चमकेगा दिनकर।

हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम करने का काम किया हैं, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है और जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा चलाए गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान जलवायु परिवर्तन के प्रति सटीक जवाब हैं।

मध्यप्रदेश भारत का लंग्स है जो पूरे देश को आक्सीजन देने का काम करता है। प्रदेश का 31 प्रतिशत क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है और पूरे देश का कुल 12 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर मध्यप्रदेश में हैं, जिससे मध्य प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क और 24 अभ्यारण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कूनो अभ्यारण्य में चीते भी लाए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जी-20 में वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस जैसे कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। जिससे यूएन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को ''चैंपियन ऑफ अर्थ'' का पुरस्कार भी दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कॉप 28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रस्तावित किया हैं। पेट्रोल और डीजल में 20 प्रतिशत एथेनॉल की ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। पूरे देश में 2025 तक पेट्रोल और डीजल में 20 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाएगी। बायोमास को बायोफ्यूल बनाए जाने के लिए 12 से ज्यादा रिफाइनरी डाली गई हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20 हजार करोड़ का प्रोग्राम बनाया गया है। इसी प्रकार एक नहीं अनेक पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा इनीशिएटिव लिए गए हैं। श्री मोदी द्वारा ही गुजरात में सर्वप्रथम पर्यावरण विभाग बनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश, सुरक्षित, समृद्ध, आधुनिक और पूरी दुनिया में नंबर वन बनेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मध्यप्रदेश में अधोसंरचना, शिक्षा, आर्थिक स्थिरता आदि क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा मध्यप्रदेश में 3 लाख 65 हजार करोड़ राशि का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। जो किसान और विकास दोनों के मध्य संतुलन को दर्शाता है। ▪

एक पेड़ 10 पुत्रों के समान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मालवा में "डग-डग रोटी पग-पग नीर" की कहावत है। यहां अनगिनत वृक्ष हुआ करते थे, जो काल के प्रवाह में खत्म होते चले गए। मालवा में कई सारी नदियां जैसे - चंबल, शिप्रा, गंभीर और अन्य सात नदियां इंदौर से निकलती हैं। एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। इस प्रकार से इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाने का जो रिकॉर्ड बना है वह अभूतपूर्व है। मालवा की संस्कृति में प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर रखने का रिवाज है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने बहुत व्यापक रूप ले लिया है। अभियान अंतर्गत इंदौर में 51 लाख, भोपाल में 40 लाख और उज्जैन में 10 लाख पौधे लगाए जा रहें हैं।

तीसरा टर्म मतलब तीन गुना स्पीड - पीएम मोदी

देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में, हमें चुना हैं।

कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है।

हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रेक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण- भाव से 'जनसेवा ही प्रथम सेवा' इस मंत्र को कृतार्थ करते हुए, हमने जो कार्य किया है उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब- गरीबी से बाहर निकले हैं। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में, इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है।

हम 2014 में जब पहली बार जीतकर के आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति zero tolerance रहेगा। और मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो zero tolerance नीति है, देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत की तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य nation first है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हर निर्णय, हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम और भारत प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक reform थे, उस reform को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है।

हमारा करप्शन के प्रति zero tolerance रहेगा। और मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है।

ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो zero tolerance नीति है, देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत की तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है।

हम उस सिद्धातों को समर्पित हैं जिसमें भारत के संविधान के स्प्रिट के अनुसार सर्वपंथ समभाव उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने प्रयास किया है।

इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार secularism का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन। गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में secularism होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठाकर के मोहर लगा दी है।

Appeasement ने देश तबाह करके रखा है और इसलिए हमने justice to all, appeasement to none इस सिद्धांत को लेकर के चले हैं।

10 साल के हमारे कार्यकाल को देखने, परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है।

इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रतापूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।

देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है। हमारी नीयत, हमारी निष्ठा उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है।

इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभनिष्ठा के साथ, जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को चार चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बनाकर के देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। जब देश विकसित होता है तब कोटि-कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि-कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं।

जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है।

विकसित भारत का सीधा-सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों के quality of life में सुधार ये स्वाभाविक हमें विकसित भारत होने से देश के कोटि-कोटि जनों के भाग्य में आता है। आजादी के बाद देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है।

जब विकसित भारत होता है तब गांव की स्थिति, शहरों की स्थिति उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है। गांव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के नए-नए अवसर भी होते हैं। शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में उभरता है तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे ये हमारा सपना है।

विकसित भारत का मतलब होता है कोटि-कोटि नागरिकों को कोटि-कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं। अनेक-अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने कौशल, अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है।

मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं उस संकल्प की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और समय का पल-पल और शरीर का कण-कण देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24 by 7 for 2047. हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे।

2014 के उन दिनों को याद कीजिए, 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे में 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों को आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुँह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता, उस समय हर जगह पर ये सात शब्द सुनाई देते थे। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के ये सात शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय हर आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। और सैंकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों की घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का ये कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। एक रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डूबा दिया था। पॉलिसी paralysis था। भाई- भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिती पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो हजारों रुपयों की रिश्वत देनी पड़ती थी।

अरे गैस के कनेक्शन के लिए, Member Parliament के यहां, सांसदों के यहां अच्छे अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे। और वो भी बिना कट लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे।

मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए। हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भाई - बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष देकर के, अपने नसीब को दोष देकर के जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे।

वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो सात शब्द हिन्दुस्तान के जन मन में स्थिर हो चुके थे। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना था और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं। लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी वो थी देश निराशा की गर्त में से निकलकर के आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और उसके कारण वो सब वक्त के जो शब्द थे देश की युवा पीढ़ी की dictionary से निकलने लगे। धीरे- धीरे देश के मन में स्थिर हो गया। जो 2014 से पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वो कहने लगे कि अब इस देश में सब कुछ हो सकता है, इस देश में सब कुछ संभव है। ये विश्वास जताने का काम किया हमने। सबसे पहले तेज 5जी रोल आउट हमने दिखाया। आज देश कहने लगा तीव्र गति से 5जी का रोल आउट होना, देश गौरव से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है।

वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों-बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक पुनरक्षण आज coal production के विक्रम हुए हैं। और इसी के कारण देश अब कहने लगा है- अब भारत कुछ भी कर सकता है।

वो एक समय था 2014 के पहले फोन बैंकिंग करके बड़े-बड़े बैंक घोटाले किये जा रहे थे। अपनी personal property की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था।

2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा प्रमाणिकता की और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई। और लोगों की सेवा करने के लिए।

2014 के पहले वो भी एक वक्त था जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 2014 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे। हिन्दुस्तान के कोने-कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। 2014 के बाद का हिन्दुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सामर्थ्य दिखा दिया है।

देश का एक-एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है।

आर्टिकल 370, इसकी पूजा करने वाले

लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू-कश्मीर के जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पर रखकर के नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते थे। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया करते थे और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूबकर के कहते थे, अब तो जम्मू-कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़-चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़-चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये साफ-साफ दिखाई देता है।

140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, ये उम्मीद और जब विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है।

ये विश्वास विकसित भारत, संकल्प से सिद्धि का विश्वास है।

जब आजादी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था। जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आजादी लेकर रहेंगे, आज देश के कोटि-कोटि जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नींव इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है। जो ललक आजादी के आंदोलन में थी, वो ही ललक विकसित भारत के इस सपने को साकार करने में है।

आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट हैं और आज भारत ऐसी स्थिति पर 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्क बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे।

हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे।

10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पर ले गए। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे।

10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया। भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएंगी, वो चिप भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी। भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा। भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा, ये विश्वास हमारे दिल में है।

हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे। हम विकास की नई ऊंचाइयों को, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेंगी, हमारे पैर देश के जनसामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे, और हम चार करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं। आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से तीन करोड़ और घर बना करके इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना न पड़े, ये हम देखेंगे।

दस साल में women self help group में देश की कोटि-कोटि बहनों को entrepreneur के क्षेत्र में एक बहुत सफलता पूर्वक हम आगे बढ़े हैं। उसको next level पर ले जाने वाले हैं। women self help group में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतना बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में तीन करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले करके चलने वाले हैं।

मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं- हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम तीन गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम तीन गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को तीन गुना परिणाम लाकर दे देंगे।

एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है। और 60 साल के बाद आया है। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है। कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही ये राजनीति के खेल से नहीं होता है। जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है।

जनता ने स्थिरता और निरंतरता, इसके लिए जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ-साथ देश में चार राज्यों के भी चुनाव हुए हैं और चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। शानदार विजय प्राप्त की है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने भरपूर आशीर्वाद दिया है।

आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। सूक्ष्म दर्शन यन्त्र में भी ये नजर नहीं आते हैं।

अरुणाचल प्रदेश, हम फिर एक बार सरकार बनाएंगे। सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचण्ड विजय पाया है।

बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व से केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते हैं। तमिलनाडु में कई सीटों पर बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछले बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में तीन राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव हैं उसमें से तीन की मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड यहां चुनाव आ रहे हैं।

पिछली विधानसभा में इन तीन राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे। इस लोकसभा चुनाव में इन तीन राज्यों में हमें उससे भी ज्यादा वोट मिले थे।

पंजाब में भी हमारा अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है।

2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और देश का जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाएं तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।

कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है, जब लगातार तीन बार, कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर-आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम दिन-रात बिजली जला करके हिन्दुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।

ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर के निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मगज ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम

कर रहा है।

1984, उस चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 1984 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंस गए हैं।

एक किस्सा याद आता है, 99 मार्कस लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और वो सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो? ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक-बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है।

कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होंगी, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना?

13 राज्यों में 0 सीटें आईं हैं, अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आईं हैं पर हीरो तो है ना?

अरे पार्टी की लुटिया तो डुबोई है, अरे मौसी पार्टी अभी भी सांसे तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो।

मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल हैं, उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है।

अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती-फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

मैं कुछ आंकड़े इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां-जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1-2-3 सीटें थीं वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26 परसेंट है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ कर के चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी उनका स्ट्राइक रेट 50 परसेंट है। और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोटर शेयर इस चुनाव में गिर चुका है।

गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन तीन राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, 64 में से 2. इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़कर के ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर ना खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था।

ऐसे समय एक अवसर आया देश ने विकास के रास्ते को चुना है, देश ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का मन बना लिया है। तब भारत को एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर तय करना है। ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6-6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के दक्षिण के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। कांग्रेस पार्टी खुले आम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नए-नए narrative जड़ रही है। नयी नयी अफवाहें फैला रही है।

देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं।

कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची-समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए ये खेल जानबूझकर के खेला जा रहा है। मंचों से साफ-साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी। लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए। ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। CAA को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी eco-system इस बात को बल देती रही क्योंकि उनकी राजनीतिक मकसद पूरे हो।

देश को दंगों में झोंकने के भी प्रयास पूरे देश ने देखें हैं।

आजकल sympathy gain करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है, मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर-जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा और जोरो-जोरो से रोने लगा, मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी लेकिन वो बता नहीं रहा था बस रो रहा था मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुराकर के खा गया था। हमने सदन में यही बचकाना हरकत देखी हैं। यहां बालक बुद्धि विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा। ये चल रहा था।

Sympathy हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपये, उसकी हेरा-फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व पर अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं, और वो केस चल रहे हैं।

बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और ना ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती हैं तो सदन के अंदर बैठकर के आंखें मारते हैं। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे न हो पाएगा।

तुलसीदास जी कह गए हैं,

झूठइ लेना झूठइ देना।
झूठइ भोजन झूठ चबेना।

कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना जिसको लहू मुंह पर लग जाता है वैसे कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक चैक कर रहे थे। कि 8500 रुपए आए कि नहीं आए। ये झूठ नेरेटिव का परिणाम देखिए कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं-बहनों को हर महीने 8500 रुपए देने का झूठ इन माताओं के, बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना वो श्राप बनकर के ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है।

ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एचएएल को लेकर के झूठ, एलआईसी को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा।

संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीतकर के आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे ये शोभा नहीं देता है। जो दल साठ-साठ साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है। जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है। वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन ले तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है इसका सबूत मिल रहा है। सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारा संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों को अपमान है। देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को अपमान है।

इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर के, बालक बुद्धि मानकर के अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं हैं, इरादे गंभीर खतरे के हैं और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं।

इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है।

ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है।

कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला है। मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, बड़ी नम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। देशवासियों को भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है।

आपातकाल, इमरजेंसी का ये 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न-विछिन्न करने का पाप किया था।

सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारनामे संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक-एक शब्द के खिलाफ थे। ये वो लोग हैं, जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है।

और इसी कारण से बाबा साहेब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण, नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका, ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। अनुसूचित जातियों की उपेक्षा इसने बाबा साहब अंबेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी।

पहले षडयंत्र पूर्वक बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया।

हराया इतनी ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के इस पराजय की, उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई और खुशी उन्होंने व्यक्त की।

एक पत्र में ये लिखित है इस खुशी का, बाबा साहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम जी के पीएम बनने की संभावना थी। इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालात में पीएम न बनें। और एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। अगर बन गए तो वो हटेंगे नहीं जिंदगी भर। ये इंदिरा गांधी जी का quote उस किताब में है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी यही व्यवहार किया, उनको भी नहीं छोड़ा था। पिछड़ों के नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बिहार के सपूत सीताराम केसरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का पाप इसी कांग्रेस ने किया।

कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण की घोर विरोधी रही है। नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर के साफ-साफ शब्दों में आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट ठंडे बक्से में सालों तक दबाए रखा था।

कांग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी और जब विपक्ष में थे, उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था। वो आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था। ''मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं, जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है।'' 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था।

हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसकी विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है।

गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये हैं आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत, इस देश के हिंदुओं के साथ ये कारनामे।

ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं। ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया, ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा।

एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसको गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं।

हम बचपन से सीखते हुए आए हैं। गांव का हो और शहर होता हो, गरीब हो, अमीर हो, इस

देश का हर बच्चा-बच्चा ये जानता है। ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं, उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। हमारे देवी-देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल। ये देश कैसे माफ कर सकता है।

क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा।

हमारी सेनाएं देश का अभिमान हैं। सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की वीरता पर गर्व है। और आज सारा देश देख रहा है हमारी सेनाएं, हमारा डिफेंस सेक्टर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ इतने ही रिफॉर्म हो रहे हैं। हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर चुनौती को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे सके इसलिए युद्ध के सामर्थ्य वाली सेना बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, देश की सुरक्षा का मकसद लेकर के। बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। सीडीएस का पद बनने के बाद integration और सशक्त हुआ है।

हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से जो लंबे समय से युद्ध शास्त्रों के निषादों का मत था कि भारत में theatre command जरूरी है। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी theatre command की दिशा में प्रगति हो रही है।

आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये बातें सार्वजनिक कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगाकर के बैठा हूं।

देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। ऐसे रिफॉर्म का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं। संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिसको निभाने के लिए गालियां खाकर के भी, झूठे आरोप सहकर के भी मुंह पर ताला लगाकर हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना सशक्त बनाने के ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। ये डिफेंस रिफॉर्मस के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।

दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए वही तरीका था जिसने देश की सेना को कमजोर किया है। ये देश की सेनाओं को कमजोर किया। जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने देश आजाद हुआ, तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है।

वो भी एक वक्त था, कांग्रेस के एक जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसको कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे। विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे हैं। जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयर फोर्स तक न पहुंच पाए, इसके लिए साजिशें की गईं और ये बालक-बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे-छोटे खिलौने बना करके उड़ाने में मजा लेते थे, देश की सेना का मजाक उड़ाते थे।

कांग्रेस ऐसे हर कदम का हर रिफॉर्म का विरोध करती है, जो भारत की सेना को मजबूती दे, भारत की सेना को मजबूत बनाएं।

अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि लोग, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाएं, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है।

आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है? किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं?

वन रैंक वन पेंशन को लेकर के देश के वीर जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया।

हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने इस वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर सेवा से निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गईं। लेकिन उनका इरादा था, हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और भारत के पास संसाधन कितने भी सीमित क्यों न हो लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिये गए।

आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने उद्बोधन में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्धस्तर पर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केन्द्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए, हर घर जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है।

हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है।

भारत की विश्व में जैसे-जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है।

ये युग हरित युग है। ये युग ग्रीन ऐरा का है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है, उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने ये बीड़ा उठाया है। हमने रिनिवेबल एनर्जी का भारत पावर हाउस में, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है।

भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई-व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पर जाना है।

जितना निवेश भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए

हुआ है, वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसका अब विस्तार हो, उसको एक नए रंग रूप मिलें, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी सवरें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है।

आज भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग मैं जी-20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं कि ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही हैं और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत हैं, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी पर हमला कर रही है और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है। ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चिंता सिर्फ ट्रेजरी बेंच की नहीं है।

देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सब कोई इन बातों से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट का ये quote देश के करोड़ों-करोड़ों लोगों के लिए भी कैसे-कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही हैं, इसकी तरफ इशारा करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़ी गंभीरतापूर्वक कहा है और मैं quote पढ़ता हूं- ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है- इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट का ये quote है।

सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है इस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

भारत में भी कुछ लोग हैं, जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं। देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है।

2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का eco-system भी रहा है। ये eco-system से मिली खाद्य-पानी इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये eco-system 70 साल तक फला-फूला है। इस eco-system को चेतावनी देता हूं। मैं इस eco-system को चेताना चाहता हूं, ये eco-system की जो हरकतें हैं, जिस तरह eco-system ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को de-rail कर देंगे। मैं आज eco-system को बता देना चाहता हूं, उस हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ये देश, देश-विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।

ये ऐसा कालखंड है, जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है, हर बारीकी को नोटिस कर रही है।

अब चुनाव हो चुके हैं, 140 करोड़ देशवासियों ने 5 साल के लिए अपना निर्णय जनादेश दे दिया है। आवश्यक है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए, इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए सभी का योगदान होना चाहिए। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप भी जिम्मेदारी के साथ आगे आइए। देशहित के विषय पर हम साथ चलें, मिलकर के चलें और देशवासियों की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहे दें।

पॉजिटिव राजनीति भारत के इस कालखंड में बहुत आवश्यक है। और मैं हमारे साथी पक्षों को भी कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के पक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आइए मैदान में good-governance पर स्पर्धा करें। जहां-जहां आपकी सरकारें हैं वो NDA की सरकारों के साथ good-governance पर स्पर्धा करें, delivery पर स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने में स्पर्धा करें। देश का भला हो जाए, आपका भी भला होगा।

आप अच्छे कामों के लिए NDA से स्पर्धा करें, आप reforms के मामलें में हिम्मत करें। जहां-जहां आपकी सरकारें हैं वो reforms में कदम बढ़ाएं और वो विदेशी निवेश को आकर्षित करें। अपने-अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए इसके लिए प्रयास करें। उनको ये अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं। और इसके लिए वो भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करें, NDA की सरकारों से स्पर्धा करें, सकारात्मक स्पर्धा करें। जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है वहां पर वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें। कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है उस स्पर्धा के लिए मैदान में आए, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो।

हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणोगतिः - यानि कर्म की गति गहन है। इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब डिबेट ऐसे जीतने के बजाय कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए।

ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था। लेकिन सीना तानकर के देश की सेवा करने के संकल्प से हम डिगे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रूकावटों से ना मोदी डरने वाला, ना ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। ▪

युवाओं को अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

नई शिक्षा नीति के जरिए विद्यार्थियों को कागजी शिक्षा नहीं वरन् जीवन में बदलाव के लिए जरूरी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस युवाओं के जीवन की दिशा तय करेंगे। श्री शाह के हाथों इन कॉलेजों का शुभारंभ वो भी मालवा की धरती से होना प्रसन्नता और गर्व की बात है। भगवान कृष्ण ने भी मालवा की भूमि में रह कर 64 कलाओं, 18 पुराणों 14 विद्याओं और चार वेदों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। छह माह से भी कम समय में इन कॉलेजों का विधिवत शुभारंभ होना सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। सभी 55 कॉलेजों में शुरू किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों और लगभग 450 करोड़ रुपयों की लागत से किए गए विकास कार्यों से विद्यार्थियों को लाभ होगा। ▪

"हर-घर तिरंगा" से गर्व का अनुभव

Olympics, हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए, Cheer for Bharat !!

Sports की दुनिया के इस Olympics से अलग, कुछ दिन पहले maths की दुनिया में भी एक Olympic हुआ है। International Mathematics Olympiad. इस Olympiad में भारत के students ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार Gold Medals और एक Silver Medal जीता है। International Mathematics Olympiad इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और Overall Tally में हमारी टीम top five में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन students के नाम हैं - पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपरा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशील माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी।

'मन की बात' में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री जी : नमस्ते साथियों। 'मन की बात' में आप सभी साथियों का बहुत- बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं?

Students : हम ठीक हैं सर।

प्रधानमंत्री जीः अच्छा साथियों, 'मन की बात' के जरिए देशवासी आप सभी के experiences जानने को बहुत उत्सुक हैं। मैं शुरुआत करता हूँ आदित्य और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं, सबसे पहले मैं आप से ही शुरू करता हूँ। Olympiad के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ share कीजिए ।

आदित्य : मुझे maths में छोटे से interest था। मुझे 6th standard Math ओमप्रकाश sir, मेरे Teacher ने सिखाया था और उन्होंने मेरे math में Interest बढ़ाया था, मुझे सीखने मिला और मुझे opportunity मिली थी।

कुछ दिन पहले maths की दुनिया में भी एक Olympic हुआ है। International Mathematics Olympiad. इस Olympiad में भारत के students ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है।

इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार Gold Medals और एक Silver Medal जीता है।

प्रधानमंत्री जीः आपके साथी का क्या कहना है?

सिद्धार्थः sir, मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैं अभी class 12th pass किया हूँ। ये मेरा second time था IMO में, मुझे भी छोटे से बहुत interest था Maths में और आदित्य के साथ जब मैं 6th में था ओमप्रकाश sir ने हम दोनों को train किया था और बहुत help हुआ था हमको और अभी मैं college के लिए CMI जा रहा हूं और Maths & CS pursue कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री जीः अच्छा मुझे बताया गया है कि अर्जुन इस समय गांधीनगर में हैं और कनव तो ग्रेटर नोएडा के ही हैं। अर्जुन और कनव, हमने, Olympiad को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा कोई विषय, और कोई विशेष अनुभव, अगर बताएंगे, तो, हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा।

अर्जुनः नमस्ते Sir, जय हिन्द, मैं अर्जुन बोल रहा हूं।

प्रधानमंत्री जीः जय हिन्द अर्जुन।

अर्जुनः मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरी mother श्रीमती आशा गुप्ता physics की professor हैं Delhi University में, और मेरे father, श्री अमित गुप्ता chartered accountant हैं। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ, और सबसे पहले, मैं, अपनी सफलता का श्रेय, अपने माता-पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि, जब एक परिवार

में कोई सदस्य एक ऐसे competition की तैयारी कर रहा होता है तो, केवल वो सदस्य का संघर्ष नहीं होता पूरे परिवार का संघर्ष होता है। Essentially हमारे पास जो हमारा paper होते हैं उसमें हमारे पास तीन problems के लिए साढ़े चार घंटे होते हैं, तो एक problem के लिए डेढ़ घंटा - तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक problem को solve करने के लिए कितना समय होता है! तो हमें, घर पे, काफी मेहनत करनी पड़ती है। हमें problems के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं, कभी-कभार तो एक एक problem के साथ, एक दिन, या यहां तक कि, 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें online problems ढूँढ़नी होती हैं। हम पिछले साल की problem try करते हैं, और ऐसे ही, जैसे हम, धीरे-धीरे मेहनत करते जाते हैं, उससे हमारा experience बढ़ता है, हमारी सब से जरूरी चीज, हमारी problem solving ability बढ़ती है, जो, ना कि हमें mathematics में, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है।

प्रधानमंत्री:- अच्छा मुझे कनव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो, ये सारी तैयारी में कोई खास जो हमारे नौजवान साथियों को बड़ा अच्छा लगे जानकर के।

कनव तलवार: मेरा नाम कनव तलवार है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। Maths मेरा पसंदीदा subject है। और मुझे बचपन से maths बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे puzzles कराते थे। जिससे मेरा interest बढ़ता गया। मैंने Olympiad की तैयारी 7th Class से शुरू की थी। इसमें मेरी sister का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे parents ने भी हमेशा मुझे support किया। ये Olympiad HBCSE conduct कराता है। और ये एक 5 stage process होता है। पिछले साल मेरा Olympiad में नहीं हुआ था और मैं काफी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे parents ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं और सफर मायने रखता है सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि - 'Love what you do and do what you love'। सफर मायने रखता है सफलता नहीं और हमें success मिलते रहेगा। अगर हम अपने subject से प्यार करें। और journey को enjoy करें।

प्रधानमंत्री:- तो कनव आप तो mathematics में भी interest रखते हैं और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है!

कनव तलवार:- जी सर ! मैं बचपन में debates और orating भी करता था।

प्रधानमंत्री:- अच्छा अब आइए हम आनंदों से बात करते हैं। आनंदों, आप अभी गुवाहाटी में हैं और आपका साथी रुशील आप मुंबई में हैं। मेरा आप दोनों से एक question है। देखिये, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूँ और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं students से संवाद करता रहता हूँ। बहुत से छात्रों को maths से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि maths से दोस्ती कैसे की जाए?

रुशील माथुर: सर ! मैं रुशील माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं, और हम पहली बार addition सीखते हैं - हमें carry forward समझाया जाता है। पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि carry forward होता क्यों हैं? जब हम compound interest पढ़ते हैं, हम ये question कभी नहीं पूछते कि compound interest का formula आता कहाँ से हैं? मेरा मानना ये है कि maths actually एक सोचने और problem solving की एक कला है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब mathematics में एक नया question जोड़ दें, तो ये question है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा क्यों होता है? तो I think इससे maths में बहुत interest बढ़ सकता है, लोगों का! क्योंकि जब किसी चीज को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि maths सब सोचते हैं कि एक बहुत logical सा subject है। पर इसके अलावा maths में बहुत creativity भी important होती है। क्योंकि creativity से ही हम out of the box solutions सोच पाते हैं, जो Olympiad में बहुत useful होते हैं। और इसलिए maths Olympiad का भी बहुत important relevance है Maths के interest बढ़ाने के लिए।

प्रधानमंत्री:- आनंदो कुछ कहना चाहेंगे!

आनंदो भादुरी: नमस्ते PM जी! मैं आनंदो भादुरी गुवाहाटी से। मैं अभी-अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ। यहाँ के local Olympiad मैं 6th और 7th में करता था। वहाँ से रुचि हुई ये मेरी दूसरी IMO थी। दोनों IMO बहुत अच्छे लगें। मैं रुशील जो था उससे मैं सहमत हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्हें maths से डर है उन्हें धैर्य की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमें maths जैसे पढ़ाया जाता है। क्या होता है एक formula दिया जाता है वो रटा जाता है फिर उस formula से ही 100 (सौ) सवाल ऐसे पढ़ने पढ़ते हैं। लेकिन formula समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता सिर्फ सवाल करते जाओ, करते जाओ। formula भी रटा जाएगा और फिर exam में अगर formula भूल गया तो क्या करेगा? इसलिए मैं कहूँगा कि formula को समझो, जो रुशील कहा था, फिर धैर्य से देखो! अगर formula ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे। एक-दो सवाल से ही हो जाएंगे और maths को डरना भी नहीं है।

प्रधानमंत्री जी: आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई, अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं?

सिद्धार्थ: बहुत सारे दूसरे देशों से interact किया था, बहुत सारे cultures थे और बहुत अच्छा था दूसरे students से interact connect, और बहुत सारे famous mathematician थे

प्रधानमंत्री जी: हाँ आदित्य

आदित्य:- बहुत अच्छा experience था और हमें उन्होंने Bath city को घुमा के दिखाया था और बहुत अच्छे-अच्छे views दिखे थे, parks लेके गए थे और हमें oxford University को भी लेके गए थे। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था।

प्रधानमंत्री जी: चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बात करके, और मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि, मैं जानता हूँ इस प्रकार के खेल के लिए काफी focus activity करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है, और परिवार के लोग भी कभी-कभी तंग आते हैं - ये क्या गुणा-भाग, गुणा-भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आप को बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने देश का मान बढ़ाया, नाम बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों।

Students: Thank You, धन्यवाद।

प्रधानमंत्री जी : Thank You.

Students: Thank You Sir, जय हिन्द।

प्रधानमंत्री जी:- जय हिन्द - जय हिन्द।

आप सभी Students से बात करके आनंद आ गया। 'मन की बात' से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि maths के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद, दूसरे युवाओं को maths को enjoy करने की प्रेरणा मिलेगी।

'मन की बात' में, अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं, जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने चराईदेउ

मैदाम का नाम सुना है? अगर नहीं सुना, तो अब आप ये नाम बार-बार सुनेंगे, और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराईदेउ मैदाम को NESCO World Heritage Site में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं, लेकिन Northeast की पहली साइट होगी।

आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेउ मैदाम आखिर है क्या, और ये इतना खास क्यों है। चराईदेउ का मतलब है shining city on the hills, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदाम में रखते थे। मैदाम, टीले नुमा एक ढांचा होता है, जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है, और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदाम, अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी।

अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेंगी। 13वीं शताब्दी से शुरू होकर ये साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे, कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि, इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक, महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान, अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदाम में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराईदेउ मैदाम के World Heritage Site बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने travel plans में इस site को जरूर शामिल करिएगा।

अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है - Project PARI... अब आप परी सुनकर confuse मत होईएगा.. ये परी स्वर्गीय कल्पना से नहीं जुड़ी बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। PARI यानि 'Public Art of India' Project PARI, public art, को

लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे.. सड़कों के किनारे, दीवारों पर, underpass में बहुत ही सुंदर paintings बनी हुई दिखती हैं। ये paintings और ये कलाकृतियाँ यही कलाकार बनाते हैं जो PARI से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे Culture को और ज्यादा popular बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत art works आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ underpass और flyover पर भी आप ऐसे खूबसूरत Public Art देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी Public Art पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा।

'मन की बात' में, अब बात, 'रंगों की' - ऐसे रंगों की, जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की ढाई-सौ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी-छोटी दुकानें और छोटे-मोटे काम कर गुजारा करती थी। लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने 'UNNATI Self Help Group' से जुड़ने का फैसला किया, और इस group से जुड़कर, उन्होंने block printing और रंगाई में training हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही हैं। इनके बनाए Bed Cover, साड़ियाँ और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है।

रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में कारीगर, Handloom को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चाहे ओडिशा की 'संबलपुरी साड़ी' हो, चाहे MP की 'माहेश्वरी साड़ी' हो, महाराष्ट्र की 'पैठाणी' या विदर्भ के 'Hand block prints' हों, चाहे हिमाचल के 'भूट्टिको' के शॉल और ऊनी कपड़े हों, या फिर, जम्मू-कश्मीर के 'कनि' शॉल हों। देश के कोने-कोने में handloom कारीगरों का काम छाया हुआ है। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम 'National Handloom Day' मनाएंगे। आजकल, जिस तरह handloom उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है। अब तो कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से handloom उत्पाद और Sustainable Fashion को बढ़ावा दे रही हैं। Kosha AI, Handloom India, D-Junk, Novatax, Brahmaputra Fables, ऐसे कितने ही Start-up भी handloom उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे local products को popular बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने local products को 'हैशटैग माई प्रॉडक्ट माई प्राइड' के नाम से Social Media पर upload करें। आपका ये छोटा सा प्रयास, अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा।

handloom के साथ-साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूँगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। मुझे ये बताते हुए भी आनंद आ रहा है - खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार डेढ़ लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गया है। डेढ़ लाख करोड़ रुपए!! और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है ? 400% (परसेंट)। खादी की, handloom की, ये बढ़ती हुई बिक्री, बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस industry से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी, उन्हीं को

हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति-भांति के वस्त्र होंगे, और आपने, अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे, तो, इस साल से शुरू कर लें। अगस्त का महीना आ ही गया है ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा - खादी खरीदने के लिए।

'मन की बात' में मैंने अक्सर आपसे Drugs की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा drugs की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए, सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है, जिसका नाम है - 'मानस'। Drugs के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही 'मानस' की Helpline और Portal को launch किया गया है। सरकार ने एक Toll Free Number '1933' जारी किया है। इस पर Call करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर rehabilitation से जुड़ी जानकारी ले सकता है। अगर किसी के पास Drugs से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है, तो वो, इसी नंबर पर call करके 'Narcotics Control Bureau' के साथ साझा भी कर सकते हैं। 'मानस' के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को 'Drugs free' बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि MANAS Helpline का भरपूर उपयोग करें।

भारत में तो Tigers 'बाघ', हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से- कहानियाँ सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गाँव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गाँव है, जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती। लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति आती है, वहाँ भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन-भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है 'कुल्हाड़ी बंद पंचायत'। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ 'कुल्हाड़ी बंद पंचायत' अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल, एक बार फिर से हरे-भरे हो रहे हैं, और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है।

महाराष्ट्र का Tadoba-Andhari Tiger Reserve बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति के हमारे भाई-बहनों ने Eco-tourism की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियाँ बढ़ सके। आपको आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले 'चेन्चू' जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने Tiger Trackers के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के movement की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही, वे, क्षेत्र में, अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा 'बाघ मित्र कार्यक्रम' भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को 'बाघ मित्र' के रूप में काम करने की training दी जाती है। ये 'बाघ मित्र' इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति ना बने। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने, यहाँ, कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है लेकिन मुझे खुशी है कि जन-भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनियाभर में जितने बाघ हैं उनमें से 70 प्रतिशत बाघ हमारे देश में हैं। सोचिए! 70 प्रतिशत बाघ!! - तभी तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई Tiger Sanctuary है।

बाघ बढ़ने के साथ-साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले 'मन की बात' कार्यक्रम में आपसे 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध, इंदौर में, एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़ें और Selfie लेकर Social Media पर भी post करें। इस अभियान से जुड़कर आपको, अपनी माँ, और धरती माँ, दोनों के लिए, कुछ special कर पाने का एहसास होगा।

15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है। और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, 'हर घर तिरंगा अभियान'। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में 'हर घर तिरंगा अभियान' के लिए सबका जोश high रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ Selfie लेकर Social Media पर post करने का craze भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब colony या society के एक-एक घर पर तिरंगा लहराता है, तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी 'हर घर तिरंगा अभियान' - तिरंगे की शान में एक Unique Festival बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह-तरह के innovation भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते-आते, घर में, दफ्तर में, कार में, तिरंगा लगाने के लिए तरह-तरह के product दिखने लगते है। कुछ लोग तो 'तिरंगा' अपने दोस्तों, पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है।

पहले की तरह इस साल भी आप 'harghartiranga.com' पर तिरंगे के साथ अपनी Selfie जरूर upload करेंगे और मैं, आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या NaMo App पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के सम्बोधन में cover करने की कोशिश करूंगा। ▪

वीरांगना रानी अवंती बाई

रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थीं। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। ये लोधी समाज की महावीरांगना थीं।

रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थीं। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। ये लोधी समाज की महावीरांगना थीं। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे इतिहास जगत अनभिज्ञ है। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद राजकुमार विक्रमादित्य सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेहणी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंती बाई से हुआ। विक्रमादित्य सिंह बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे और पूजापाठ एवं धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते। अतः राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती रहीं। उनके दो पुत्र हुए अमान सिंह और शेर सिंह। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों में अपने पैर जमा लिए थे।

रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत सिंह को विक्षिप्त तथा अमान सिंह और शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ राज्य को हड़पने की दृष्टि से अंग्रेज शासकों ने 'कोर्ट ऑफ वार्ड्स' की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त कर शेख मोहमद तथा मोहमद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा। जिससे रामगढ़ रियासत 'कोर्ट ऑफ वार्ड्स' के कब्जे में चली गयी। अंग्रेज शासकों की इस हड़प नीति का परिणाम भी रानी जानती थी, फिर भी दोनों सरबराहकारों को उन्होंने रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। 1855 ई. में राजा विक्रमादित्य सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। अब नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में राज्य शक्ति रानी के हाथों आ गयी। रानी ने राज्य के कृषकों को अंग्रेजों के निर्देशों को न मानने का आदेश दिया, इस सुधार कार्य से रानी की लोकप्रियता बढ़ी।

1857 ईस्वी में सागर एवं नर्मदा परिक्षेत्र के निर्माण के साथ अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि हुई। अब अंग्रेजों को रोक पाना किसी एक राजा या तालुकेदार के वश का नहीं रहा। रानी ने राज्य के आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों और बड़े मालगुजारों का विशाल समेलन रामगढ़ में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता गढ़ पुरवा के राजा शंकरशाह ने की। गुप्त सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रचार का दायित्व रानी पर था। एक पत्र और दो काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित करना। पत्र में लिखा गया 'अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियों पहनकर घर में बैठो।' पत्र सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था तो चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का सशक्त माध्यम बनी। पुड़िया लेने का अर्थ था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना समर्थन देना।

देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांति का शुभारंभ हो चुका था। 1857 में 52वीं देशी पैदल सेना जबलपुर सैनिक केन्द्र की सबसे बड़ी शक्ति थी। 18 जून को इस सेना के एक सिपाही ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी पर घातक हमला किया। जुलाई 1857 में मण्डला के परगनादार उमराव सिंह ठाकुर ने कर देने से इनकार कर दिया और इस बात का प्रचार करने लगा कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेज, विद्रोहियों को डाकू और लुटेरे कहते थे। मण्डला के डिप्टी कमिश्नर वाडिंग्टन ने मेजर इस्काइन से सेना की मांग की। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों की हलचलें बढ़ गईं। गुप्त सभाएं और प्रसाद की पुड़ियों का वितरण चलता रहा। इस बीच राजा शंकरशाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को दिए गए मृत्युदण्ड से अंग्रेजों की नृशंसता की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वे इस क्षेत्र के राज्यवंश के प्रतीक थे। इसकी प्रथम प्रतिक्रिया रामगढ़ में हुई। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाना में चढ़ाई कर दी। जिससे थाने के सिपाही थाना छोड़कर भाग गए और विद्रोहियों ने थाने पर अधिकार कर लिया। रानी के सिपाहियों ने घुघरी पर चढ़ाई कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के तालुकेदार धन सिंह की सुरक्षा के लिए उमराव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी।

मण्डला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। अवंतीबाई लोधी ने मण्डला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की सूचना प्राप्त होने पर शहपुरा और मुकास के जमींदार भी मण्डला की और रवाना हुए। मण्डला पहुंचने के पूर्व खड़देवरा के सिपाही भी रानी के सिपाहियों से मिल गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंती बाई का युद्ध हुआ। वाडिंग्टन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मण्डला छोड़ सिवनी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मण्डला जिला एवं रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया।

अंग्रेजी सेनाएं रामगढ़ विजय के बाद देवहारगढ़ की ओर रवाना हुईं। यहां रानी की सहायता के लिए शहपुरा एवं शाहपुर के जमींदार भी पहुंच चुके थे। देवहारगढ़ को अंग्रेज सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। क्रांतिकारियों और अंग्रेजी सेना के मध्य निर्णायक युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक दोनों के मध्य युद्ध चलता रहा। रानी भी घायल हो चुकी थी। सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। आगे युद्ध करना और स्वयं को सुरक्षित रखना कठिन हो गया। 20 मार्च 1858 रानी ने आत्मसमान की रक्षा के लिए गिरधारी नाई की कटार छीनकर घुनसी नाले के निकट आत्मोत्सर्ग कर दिया। रानी का बलिदान हो गया, फिर भी मुक्ति आंदोलन में ठहराव नहीं आया। यह क्रांति मात्र रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की नहीं थी, अपितु संपूर्ण क्षेत्र की थी, क्षेत्र की प्रजा की थी। ▪

नारी शक्ति की प्रतीक हैं देवी अहिल्या

देवी अहिल्या बाई रणनीति के साथ कूटनीति में भी चतुर थी, उन्होंने राघोबा को जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है: तुम मेरा राज्य छीनने की बड़ी भूल कर रहे हो। तुमने मुझे अबला समझा है, परन्तु शायद तुम्हे यह नहीं मालूम की मैं कैसी अबला हूँ? ये तो तुम्हें रणभूमि में ही पता चलेगा।

देवी अहिल्या बाई होल्कर को लोकमाता के स्वरूप में मालवा क्षेत्र की जनता नमन करती थी। चाहे उस समय अर्थात सन् १७०० में लोकतांत्रिक पद्धति नहीं थी, लेकिन राजधर्म के अनुसार शासन संचालन देवी अहिल्या बाई ने किया। उनका जीवन धर्म संस्कृति के लिए था। वे जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन चलाती थी। वे शक्ति की भी प्रतीक थी। राघोबा जो पेशवा के सूबेदार थे। उन्होंने होल्कर राज्य हड़पने की साजिश रची। वे सेना लेकर मालवा में आये और उन्होंने होल्कर राज्य का शासन सम्हालने का ऐलान करवा दिया। राज्य की जनता देवी अहिल्या बाई को चाहती थी। अहिल्या बाई ने मुकाबले के लिए सैनिक तैयारी प्रारंभ कर दी। उनकी अपनी महिला सेना थी। भोंसले और गायकवाड़ की सेना भी देवी अहिल्या की सहायता के लिए आ गई। क्षिप्रा के उस पार राघोबा की सेना ने डेरा डाल रखा था।

देवी अहिल्या बाई रणनीति के साथ कूटनीति में भी चतुर थी, उन्होंने राघोबा को जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है तुम मेरा राज्य छीनने की बड़ी भूल कर रहे हो। तुमने मुझे अबला समझा है, परन्तु शायद तुम्हे यह नहीं मालूम की मैं कैसी अबला हूँ? ये तो तुम्हें रणभूमि में ही पता चलेगा। मैं तुमसे रणभूमि में भेंट करने आ रही हूं। तुम्हारी मर्दानगी का मुकाबला अपने वीर जांबाजों से नहीं कराऊंगी, तुम्हारे लिए मेरी महिला सेना ही काफी है। यदि आप हमारी महिला सेना से हार गये तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यदि मैं हार गई तो कोई मेरी हंसी नहीं उड़ायेगा। सभी आप पर ही थूथू करेंगे। फिर तुम्हारे सिर पर ऐसा कलंक का टीका लगेगा, जिसे तुम कभी नहीं भुला पाओगे। सोच समझकर ही लड़ाई का निर्णय लेना, राघोबा। इसके बाद राघोबा ने लड़ाई का विचार छोड़कर देवी अहिल्या को बेटी कहना शुरू किया और वे इंदौर में होल्कर राज्य के मेहमान बनकर कुछ दिन रहे।

देवी अहिल्या परंपरा, धर्म को मानने वाली दयालू महिला थी, उन्होंने मंदिर, घाट, धर्मशाला आदि प्रायः सभी तीर्थों में निर्माण कराये। रामेश्वरम, काशी, सोमनाथ आदि तीर्थों में देवी अहिल्या के द्वारा निर्मित घाट, मंदिर, धर्मशाला स्थित है। उन्होंने इन धार्मिक कार्यों के लिए 'रवासगी' ट्रस्ट बनाया। रामराज्य, धर्मराज्य और स्वर्णयुग की तुलना देवी अहिल्या के प्रशासन से की जाती है। पहले होल्कर राज्य की राजधानी नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर में रही। देवी अहिल्या ने इंदौर में भी प्रशासन चलाया। राजवाड़ा, छत्रियां देवी अहिल्या की स्मृति ताजी करती है। मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर को देवी अहिल्या की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर हर वर्ष अहिल्या उत्सव मनाता है। ▪

क्रांतिवीर मदनलाल ढींगरा

लंदन में ढींगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग ढींगरा की प्रचण्ड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। मदनलाल उच्च शिक्षण हेतु लंदन में रहते थे। उस समय सावरकरजी भी वहीं पर थे, उस समय सावरकर जी को एक भोजन प्रसंग में रंगभेद का अनुभव हुआ।

उन्हें अंग्रेजों द्वारा उनके साथ न बैठ अलग टेबल पर बैठने को कहा गया। ज्वलंत देशाभिमान और अत्यंत स्वाभिमानी सावरकरजी को यह बात सहन नहीं हुई और वह वहां से बाहर चले गए।

मदनलाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सेनानी थे। वे इंग्लैण्ड में अध्ययन कर रहे थे। जहां उन्होने कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना बीसवीं शतादी में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोंलन की कुछेक प्रथम घटनाओं में से एक है। मदललाल ढींगरा का जन्म सन् 1883 में पंजाब में एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरे रंगे हुए थे, परंतु माताजी अत्यन्त धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थीं। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। जब मदनलाल को भारतीय स्वतंत्रता सबन्धी क्रान्ति के आरोप में लाहौर के एक विद्यालय से निकाल दिया गया, तो परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ लिया। मदनलाल को एक क्लर्क रूप में, एक तांगाचालक के रूप में और एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। वहां उन्होंने एक यूनियन (संघ) बनाने का प्रयास किया, परंतु वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में भी काम किया। अपने बड़े भाई से विचार विमर्श कर वे सन् 1906 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गये जहां युनिवर्सिटी कालेज लंदन में यांत्रिक प्रौद्योगिकी (Mechanical Engineering) में प्रवेश लिया । इसके लिए उन्हें उनके बड़े भाई एवं इंग्लैंड के कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहायता मिली। लंदन में ढींगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग ढींगरा की प्रचण्ड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। मदनलाल उच्च शिक्षण हेतु लंदन में रहते थे। उस समय सावरकरजी भी वहीं पर थे, उस समय सावरकर जी को एक भोजन प्रसंग में रंगभेद का अनुभव हुआ। उन्हें अंग्रेजों द्वारा उनके साथ न बैठ अलग टेबल पर बैठने को कहा गया। ज्वलंत देशाभिमान और अत्यंत स्वाभिमानी सावरकरजी को यह बात सहन नहीं हुई और वह वहां से बाहर चले गए। उस समय मदनलाल और उनका एक दोस्त वहां उपस्थित था। मदनलाल जी ने सावरकरजी को समझाने का प्रयत्न किया कि इस प्रकार के वर्तन की उन्हें आदत डालनी होगी।

मदनलाल और सावरकर, यह इनकी प्रथम भेंट थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के लिए देशभक्तों ने अनेक मार्ग ढूंढ़े। अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए क्रांतिकारी मार्ग से देशभक्तो ने टक्कर देने हेतु राष्ट्ररक्षा एवं ब्रिटिशों से मुक्तता के लिए क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनवाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। मदनलाल, इण्डिया हाउस के भी सदस्य थे, जो भारतीय विद्यार्थियों के राजनैतिक क्रियाकलापों का केंद्र था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्नाई दा, सतिन्दर पाल और कांशी राम जैसे क्रान्तिकारियों को मृत्युदण्ड दिये जाने से बहुत क्रोधित थे । भारतीयों के लिए मातृभूमि को देने के लिए क्या है, तो वह स्वयं का रक्त ही है, ऐसा ढींगराजी का मानना था । मदनलालजी के विचार अत्यंत स्पष्ट थे और वह उतने ही स्पष्टता से व्यक्त किया करते थे, वे विदेशी शस्त्रास्त्रों की सहायता से दास्यता में जकड़े हुए राष्ट्र को बचाने के लिए निःशस्त्र होकर रणभूमि में उतरकर सामना करना कठिन होने के कारण उन्होंने घात लगाकर हमला किया। 01 जुलाई सन् 1909 में लंदन के नेशनल इंडियन असोसिएशन के वार्षिकोत्सव में कर्जन आने वाला है, इस गोपनीय समाचार की जानकारी मदनलाल को हुई।

01 जुलाई सन् 1909 की शाम को इण्डियन नेशनल एसोशिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज एकत्रित हुए। जब कर्जन वायली (भारत मामलों के सेक्रेटरी आफ स्टेट के राजनीतिक सलाहकार) अपनी पत्नी के साथ सभाग्रह में घुसे, ढींगरा ने उनके चेहरे पर पांच गोलियां दागी, इसमें से चार सही निशाने पर लगीं। ढींगरा ने अपनी पिस्तौल से अपनी हत्या करनी चाही, परंतु उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई को ढींगरा के प्रकरण की सुनवाई पुराने बेली कोर्ट में हुई। उनको मृत्युदण्ड दिया गया और 17 अगस्त सन 1909 को फांसी दे दी गयी। ▪

खुदीराम बोस

फाँसी के विचार से मुझे जरा भी दुःख नहीं है। मेरा एक ही दुःख है कि किंग्जफोर्ड को उसके अपराध का दण्ड नहीं मिला।"

ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ने के लिए अंग्रेजों पर पहला बम फेंकने वाले क्रान्तिकारी खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसम्बर, 1989 को मेदिनीपुर जिले के बहुबेनी ग्राम में हुआ। मेदिनीपुर बंगाल का एक जिला था। इनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ वसु था तथा माता का नाम था श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी। पिता नदझोल तहसील के तहसीलदार थे। इकलौते पुत्र होने के कारण खुदीराम बोस माता-पिता के लाड़ले बेटे थे पर 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें माता-पिता का विछोह सहना पड़ा। उनका पालन पोषण बड़ी बहन अनुरूपा देवी ने माँ की तरह किया। उनके जीजा अमृतलाल जी भी उनको बहुत प्यार करते थे।

देशभक्ति का भाव बालक खुदीराम में बाल्यावस्था से ही जागृत हो गया था। गोरे, लाल मुँह वाले अंग्रेजों का भारत पर शासन करना उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता था।

'आनन्दमठ' उपन्यास के रचयिता बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय मेदिनीपुर में ही शासकीय सेवा में थे। इस उपन्यास का गीत 'वन्दे मातरम्' बड़ा लोकप्रिय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इस गीत से बड़ी प्रेरणा मिलती थी। आज भी यह राष्ट्रगीत के रूप में प्रत्येक राष्ट्रीय समारोह एवं विद्यालयों में गाया जाता है। यह वन्देमातरम् का गीत ही बालक खुदीराम का प्रेरणा स्त्रोत बना।

1905 में गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने भारतीयों का मनोबल गिराने के लिए बंगाल का विभाजन किया। इस विभाजन का पूरे राष्ट्र ने एक स्वर से विरोध किया। आनन्दमठ उपन्यास से प्रेरित होकर खुदीराम बोस ने भी अपने जीवन को देश की सेवा के लिए न्यौछावर करने का संकल्प लिया। अतः वे क्रान्तिकारियों के दल में सम्मिलित हो गए। इसके लिए उन्हें अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा।

क्रान्तिकारियों के साथ खुदीराम ने पिस्तौल आदि अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करना सीखा। उन्होंने वन्दे मातरम् गाने तथा आनन्दमठ पढ़ने के लिए अपने साथियों को भी उत्साहित किया।

अंग्रेजों ने वन्दे मातरम् के बढ़ते प्रभाव को देखकर, वन्दे मातरम् कहने को राजद्रोह घोषित कर दिया। खुदीराम ने अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए मेदिनीपुर की प्रदर्शनी में वन्दे मातरम् के पर्चे बांटे तथा नारे लगाए। यह प्रदर्शनी फरवरी 1906 में आयोजित की गई थी। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ना चाहा पर वे असफल रहे। बाद में उन पर एक मुकदमा चलाया गया पर छोटी उम्र होने के कारण न्यायालय ने उन्हें कोई सजा नहीं दी।

देशभक्त विपिन चन्द्र पाल ने 'वन्दे मातरम्' पत्रिका का प्रकाशन किया। श्री अरविन्द घोष इसके संपादक नियुक्त हुए। 1907 में अंग्रेज सरकार ने वन्देमातरम् पत्रिका पर राजद्रोह का अभियोग लगाया। भारतीय युवकों ने इसका प्रबल विरोध किया। 26 अगस्त 1907 के दिन हजारों युवक कोर्ट के सामने इस अभियोग का विरोध प्रकट कर रहे थे। इस पर क्रुद्ध होकर अंग्रेज सिपाही एक युवक को अकारण पीटने लगे। 15 वर्षीय सुशील कुमार सेन ने जब इसका विरोध किया तो अंग्रेज अधिकारी उसको डाँटने लगा। बस तब क्या था। सुशील कुमार ने अंग्रेज अधिकारी की नाक पर घूँसा मारा और उन्हें न्यायाधीश किंग्जफोर्ड ने 15 कोड़े मारने की सजा दी।

क्रान्तिकारी दल ने किंग्जफोर्ड से बदला लेने का निश्चय किया। 1908 में उसकी हत्या की योजना बनाई गई। खुदीराम ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया। दल प्रमुख ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को पिस्तौल और कुछ पैसे देकर मुजफ्फरपुर की ओर रवाना किया। किंग्जफोर्ड उन दिनों वहीं सेशन जज के पद पर नियुक्त था। प्रफुल्ल कुमार चाकी रंगपुर ग्राम का रहने वाला था। वह खुदीराम की ही आयुवर्ग का तथा उसी के समान देशभक्त था। 30 अप्रैल 1908 की रात मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब के समीप किंग्जफोर्ड की घोड़ागाड़ी पर खुदीराम ने बम फेंका। पर किंग्जफोर्ड निशाना चूक जाने के कारण बच गया। उसके अतिथि कैनेडी की पत्नी, लड़की और नौकर मारे गए।

बम फेंककर खुदीराम 25 मील तक भागते चले गए पर आखिरकार वेनी रेलवे स्टेशन के पास लखा नामक स्थान पर पकड़े गए। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने पुलिस द्वारा घेरे जाने पर स्वयं को पिस्तौल से गोली मारकर राष्ट्रहित में अपनी बलि दे दी। अंग्रेज सिपाही उसका सिर काटकर मुजफ्फरपुर ले गए। खुदीराम को मृत्युदण्ड देने का आदेश दिया गया। जब उनसे बयान देने को कहा गया तो उन्होंने कहा-'राजपूत वीरों की तरह मैं देश की स्वाधीनता के लिए मरना चाहता हूँ। फाँसी के विचार से मुझे जरा भी दुःख नहीं है। मेरा एक ही दुःख है कि किंग्जफोर्ड को उसके अपराध का दण्ड नहीं मिला।'

11 अगस्त 1908 को प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फाँसी दी गई। मृत्यु के समय उनके हाथ में श्रीमदभगवदगीता थी और चेहरे पर बलिदानी की मोहक मुस्कान। फाँसी के समय इस वीर किशोर की आयु कुल अठारह वर्ष आठ महीने की थी।

मातृभूमि के प्रति खुदीराम का भाव था-

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदय,
तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारइ
प्रतिमा गड़ि,
मंदिरे मंदिरे, वन्देमातरम्। ▪

वाह रे वकील-वाह रे मुवक्किल

लोकमान्य तिलक के जीवन पर प्रकाश डालने के प्रयास में यह ध्यान में आता है कि उनके जीवन के विविध पहलुओं में से उनकी कानूनी लड़ाईयाँ एक महत्वपूर्ण सोपान हैं। लोकमान्य तिलक के जीवन में से यदि उनकी कानूनी लड़ाइयाँ हटा दी जाएँ तो सिर्फ उनकी कांग्रेस की गतिविधियां (जो सिर्फ कुल मिलाकर 8-10 साल की टुकड़ों-टुकड़ों में रहीं) एवं कुछ सामाजिक कार्य व पत्रकारिता ही शेष बचेंगे। जिसके कारण उनका जीवन कुछ और कम तेजस्वी लगने लगेगा।

तिलक के जीवन के लगभग 40 से ज्यादा वर्ष कानूनी लड़ाईयों के फेरे में ही रहे हैं। वे वकील के रूप में, आवेदक के रूप में, आरोपी के रूप में या कानून के शिक्षक के रूप में या इनमें से किसी भी रूप में अदालत के बाहर या अन्दर प्रस्तुत हुए हों उनका दबदबा हमेशा नक्षत्र मण्डल के राजा सूर्य की भाँति रहा है। कानूनी मामलों में तिलक के सभी रूपों का अध्ययन आज की पीढ़ी को शैक्षणिक किताबों में तो बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं गया है।

कानून का उपयोग हथियार के रूप में

तिलक जी सन् 1880 में एल.एल.बी की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। तिलक जी ने लगभग नौ वर्ष तक कानून की कक्षाएँ लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ाया। तिलक जी ने अपने समाचार पत्र केसरी में कई लेख सिर्फ कानून के विषयों एवं उनकी पेचीदगियों पर लिखे थे। तिलक ने कानून को अपने जीवन यापन का आधार भी बनाया था।

वे एक ऐसे अनूठे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने न केवल 40 वर्ष से ज्यादा समय कानूनी पचड़ों में बिताया वरन् यह मानकर भी चले कि अदालत कक्ष को आजादी प्राप्ति हेतु युद्ध भूमि एवं कानून को इस हेतु हथियार बनाना चाहिए। वे अक्सर कहा करते थे कि 'अंग्रेजों को उन्हीं के एक सशक्त हथियार से परास्त करूँगा।'

तिलक के मुकदमों की विशेषताएँ

तिलक के मुकदमों में राजद्रोह के आरोप के मुकदमे ऐसे प्रकरण हैं जो कानून के इतिहास में न्यायिक प्रक्रिया को अपनी युद्धनीति के भाग के रूप में उपयोग कर राजनैतिक गति प्रदान करवाने का एकमात्र उपलब्ध दस्तावेज है। तिलक पर तीन बार राजद्रोह के मुकदमे, दो बार लम्बे समय तक चले मानहानि के मुकदमे उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को अपने तीन मित्रों के तीन विभिन्न मुकदमों में बचाव के लिए गहराई तक जोड़ लिया था। एक 'ताई महाराज प्रकरण' तो जिन्दगी भर उनके पीछे लगा रहा। इस प्रकरण में ऐसे कुछ हुआ था कि एक 'बाबा महराज' नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति तिलक के मित्र थे और काफी सम्पन्न और वैभवशाली लोगों में से थे। उन्होंने अपनी मृत्यु उपरांत उपस्थित हो सकने वाली पारिवारिक परिस्थितियों को पूर्व से ही भांप कर अपनी सम्पत्ति की देखभाल हेतु तिलक महाराज (तिलक उस दौरान इसी नाम से लोकप्रिय थे) को नियुक्त कर दिया था।

वकालत व कानूनी ज्ञान की पराकाष्ठा

दिनांक 13 जुलाई, 1897 को प्रथम राजद्रोह मुकदमे में ज्यूरी ने तिलक पर 18 माह के कारावास की सजा ठोंकी थी। इसी दिन के अगली सुबह श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उपलब्ध कराए वकीलद्वय श्री गार्थ और श्री पुग प्रीव्ही काउंसिल में अपील की तैयारी हेतु बॉम्बे के एक क्लब में बैठकर योजना बना रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपना एक साथी लोकमान्य से मिलने स्थानीय कारागृह में प्रारम्भिक चर्चा के लिए भेजा। यह साथी जब वापस अंग्रेज वकील द्वय के पास आया तो उसके हाथ में लोकमान्य तिलक के द्वारा बनाया गया अपील का ड्राफ्ट था जो उन्होंने जेल में रात भर बैठकर बना डाला था। यह दोनों अंग्रेज बैरिस्टर उक्त ड्राफ्ट देखकर चकित रह गए क्या शानदार ड्राफ्टिंग थी वो, जो बिना किसी कानूनी किताबों, लेखों और कागज पत्रों की सहायता के बना दी गई थी। उन अंग्रेज वकीलों ने बाद में कहा कि उनके सम्पूर्ण वकालती जीवन में किसी भी वकील द्वारा या अन्य किसी जनसामान्य द्वारा भी बनाया गया इतना अचूक और तथ्यपरक ड्राफ्ट उन्होंने कभी नहीं देखा था जो सजा सुनने के बाद मुजरिम द्वारा ही मात्र कुछ ही घण्टों के भीतर तैयार कर दिया गया हो। यह था लोकमान्य तिलक का विलक्षण कानूनी ज्ञान।

फिर भी वकील जनसामान्य के

तिलक ने कभी जीवन यापन के लिए वकालत भले ही नहीं की हो लेकिन वे कानून को सशक्त राजनैतिक हथियार मानते थे-उनकी गणितज्ञ वाली बुद्धि कानून के पेचीदा और अकादमिक ज्ञान के विवेचन में ही उलझी रहती थी। जब वे माण्डले की जेल (जो वर्तमान में बर्मा देश में है) में राजद्रोह के मुकदमे की छह वर्ष की सजा काट रहे थे तब उन्हें ग्राम कळम्ब, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र की एक पिछड़ी धनगर (गड़रिया) जाति के गरीब किसान का पत्र मिला जिसमें उस गरीब किसान ने अपनी व्यथा लिखते हुए बताया था कि वह निचली अदालत से मुकदमा हारने पर अपनी जमीन खो रहा है और वह बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील करना चाहता है। यह व्यक्ति वैसे तो लोकमान्य के लिए अपरिचित ही था लेकिन वह इस सन्दर्भ में पूरी दुनिया में सिर्फ लोकमान्य पर ही भरोसा रखने के कारण कानूनी सलाह चाह रहा था। उसके कागज पत्रों का अध्ययन कर तिलक जी ने उसे उचित सलाह लिखकर भेजी थी।

सोचने की बात यह है कि सारा देश जानता है कि लोकमान्य तिलक ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'गीता रहस्य' इसी कारावास में लिखी थी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक गरीब किसान के लिए कानूनी सलाह भी हजारों मील दूर से भारत के दूरदराज में लिखकर भेजी थी। सचमुच में लोकमान्य ही उन सभी जन के लिए कानून स्वरूप ही थे। ऐसे विलक्षण कानूनविद् की पुण्यतिथि पर सारा देश श्रद्धा से नत है। ▪

कांग्रेस बनाम जनसंघ

आज सभी प्रकार के आदर्शों से दूर होकर कांग्रेस उस समय के नेतृत्व की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। उस स्वार्थ सिद्धि के लिए योग्यता-अयोग्यता इत्यादि का कुछ विचार नहीं रखा जा रहा है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ध्येयविहीन कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं के समक्ष यह समस्या थी कि अब कौन सी वस्तु शेष है, जिसके लिए अपनी सेवाएं समर्पित की जाएं? कांग्रेस की इस ध्येयविहीनता को महात्मा गांधी ने समझा था और इसलिए वे कांग्रेस को समाप्त कर देने पर बराबर जोर देते थे, किंतु कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कांग्रेस को अपने स्वार्थ का साधन बना लिया और उसे भंग नहीं किया।

उद्देश्य समाप्त होने पर संस्था निर्जीव हो जाती है। कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब उसे समाप्त कर देना चाहिए था। परंतु नेताओं ने इसे भी नहीं माना। फलतः मृत कांग्रेस के शव को पंडित नेहरू लिए घूम रहे हैं और उसे जिलाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस का शव अधिक सड़ जाने से गलगल कर गिरा। फलतः अनेक पार्टियों का जन्म हुआ, जिसमें पहले सोशलिस्टों का नंबर है। ये सब पार्टियों केवल विरोध के लिए बनी हैं, जिनका कोई आधार नहीं। हमें तो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक मौलिक आधार को लेना है। हम अनुरोध करने के लिए हैं, विरोध करने के लिए नहीं। जनसंघ केवल कांग्रेस के विरोध के लिए नहीं है। देश को सुखी तथा वैभवशाली बनाने का कार्य इसके सामने प्रमुख है।

कांग्रेस की ध्येयविहीनता ने देश में निराशा का वातावरण ला दिया। लोग अनुभव करने लगे कि उनका धर्म मिट रहा है, संस्कृति मिट रही है, जीवनोपयोगी वस्तुएं अन्न वस्त्र अलय हो रहे हैं। अतः जनमन में निराशा का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था। जनसंघ का उदय इस निराशावाद के वातावरण को छिन्नभिन्न कर देश में आशा और स्फूर्ति का संचार करने के लिए हुआ है।

स्वतंत्रता की लड़ाई मे कांग्रेस केवल पेशवा थी और 35 करोड़ जनता उसके साथ उस लड़ाई में संलग्न थी। नेता होने के नाते उसे स्वतंत्रता प्राप्ति का यश प्राप्त हुआ। कांग्रेस के नेता आज यह कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हमने दिलवाई है। उन लोगों से पूछना चाहिए कि योगी अरविंद जैसे लोग तथा जिन्होंने अंडमान में अपना जीवन व्यतीत किया और हंसते हुए स्वतंत्रता के लिए ही अपने जीवन की कुर्बानी की, क्या वे कांग्रेस के झंडे के नीचे आए थे? वासुदेव बलवंत फड़के कांग्रेस से बाहर ही स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। रासबिहारी बोस, भगतसिंह तथा वीर सावरकर क्या कांग्रेसी थे? सुभाष चंद्र बोस ने भी जो महान कार्य किए थे, वे भी कांग्रेस से अलग होने पर ही। परंतु इस सबका श्रेय कांग्रेस अपने ऊपर ले रही है। सच्ची बात तो यह है कि भारत की 40 करोड़ जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हम सबने इस युद्ध में भाग लिया।

आज सभी प्रकार के आदर्शों से दूर होकर कांग्रेस उस समय के नेतृत्व की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। उस स्वार्थ सिद्धि के लिए योग्यता-अयोग्यता इत्यादि का कुछ विचार नहीं रखा जा रहा है। अभी हाल में मंडी के राजा को ब्राजील का राजदूत इसलिए बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर के विरोध से अपना नाम वापस ले लिया है। पता नहीं उनमें उस पद की कहाँ तक योग्यता है।

उसी प्रकार स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कांग्रेस सरकार ने कंट्रोल लगा रखा है। यदि कंट्रोल जनता की भलाई के लिए हो तो ठीक भी है, किंतु यहाँ पर वह इसलिए है कि उसके कारण व्यापारी और पूंजीपति कांग्रेस के अँगूठे के नीचे रहते हैं। वोट लेने के समय लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं कि उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उनको याद दिलाया जाता है कि उन्हें कितने परमिट दिए गए हैं। इस प्रकार जनता को दुःख देने के लिए कांग्रेस और पूंजीपति मिल जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कांग्रेस सरकार ने 287 मन की चीनी मनमाने दामों में मिल मालिकों को बेचने की आज्ञा इसलिए दे दी थी कि उन्होंने कांग्रेस फंड में कुछ चंदा दे दिया था। कांग्रेस ने देश में तीन भयंकर भूलें की हैं। पहली, बिना किसी आदर्श के कार्य किया है, दूसरी, केवल अपनी पार्टी की स्वार्थ

सिद्धि की है, तीसरी, यदि आदर्श सम्मुख रखा भी तो वह विदेशी। उदाहरण स्वरूप यदि आज हमारे देश में अन्न की कमी है तो उसके लिए हमने विदेशों से ट्रैक्टर मंगाए किंतु यहां चलेंगे कैसे? मकानों की कमी होने पर हमने सीमेंट, लोहा और ईंट जनता को देने के बजाय मकान बनाने की फैक्टरी स्थापित की और करोड़ों रुपए फूंक दिए।

भारतीय जनसंघ का उद्देश्य भारतीय जीवन के लिए अत्यंत पवित्र और स्फूर्तिदायक है। ये सिद्धांत और आदर्श नए नहीं हैं। वे इतने पुराने हैं कि जबसे मानव मानव को पहचानने लगा, प्रकृति का प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ तथा भारत भूमि को पहचानने के साथ राष्ट्रीयता का उदय हुआ। केवल एक राष्ट्रीयता की भावना को लेकर, जिसको 'एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति' कहा गया है, जनसंघ खड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कोने-कोने में जहां जनसंघ गया है, जनता में उसका आदर हुआ है।

भारतीय जनसंघ का जन्म देश के सम्मुख एक स्वदेशीय आदर्शवाद रखने के निमित्त हुआ और उसका आधार कुछ मर्यादाओं पर स्थिर है। प्रथम तो जनसंघ भौगोलिक मर्यादा को मानता है और यह कहता है कि देश का विभाजन गलत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कहना भावनाओं को उभारना नहीं है, वरन कुछ तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसना है। आज हमारे देश में अन्न की कमी है और करोड़ों रुपयों का अन्न हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। पाकिस्तान में वह बहुतायत से है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास कोयला, लोहा और कपड़ा नहीं है, जिसके लिए उसको परेशानी होती है। पूर्वी बंगाल में जूट सड़ रहा है, पश्चिम में जूट मिलें बंद हैं। पाकिस्तान में रुई बहुतायत है, हम उसे तेज दामों पर मिस्र या अमरीका से खरीद रहे हैं। यदि दोनों देश एक हो जाएँ तो आर्थिक दृष्टि से हम फिर स्वावलंबी बन सकते हैं और हमारी सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने बजट का 55 प्रतिशत और पाकिस्तान 60 प्रतिशत केवल सेना पर व्यय कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों की आर्थिक अवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इस विभाजन के ही कारण हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहकर अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों को यह डर है कि एक के द्वारा उसका साथ छोड़ देने पर अंग्रेज दूसरे की अधिक सहायता करेगा।

सांप्रदायिक समस्या का भी हल इस विभाजन से नहीं हुआ, क्योंकि यदि कल 35 करोड़ में 10 करोड़ मुसलमान भारत में थे तो आज चार करोड़ रह गए हैं, किंतु वह समस्या हल नहीं हुई। दूसरी ओर पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं पर अत्याचार और उनका निष्कासन हमारी आर्थिक तथा राजनीतिक दशा को हर समय चिंता युक्त बनाए रखते हैं।

कश्मीर समस्या का भी सबसे सरल हल विभाजन का अंत है। इस प्रकार सब दृष्टियों से अखंडता अनिवार्य है। किंतु लोग कहते हैं कि यह बेमानी है। उत्तरी तथा दक्षिण कोरिया, मिस्र तथा सूडान और आयरलैंड इत्यादि की एकता की बात तथा उसका समर्थन करने वाले लोग भारत तथा पाकिस्तान की एकता को सुनकर केवल इसलिए बौखला जाते हैं कि उससे उनके स्वार्थों का हनन होता है। आठ साल पूर्व पाकिस्तान का बनना बेहूदा बात थी, किंतु वह बन गया। आज अखंडता 'बेहूदा' है, कल उन्हीं लोगों के सम्मुख वह भी हो जाएगा।

अखंड भारत की मांग हमारी नैतिक मांग है, क्योंकि श्री जिन्ना के अदलाबदली के प्रस्ताव को न मानकर अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की शर्त हिंदुस्थान और पाकिस्तान दोनों के लिए कांग्रेस ने रखी थी। उस समय महात्माजी ने कहा था कि इस शर्त के पूरे न होने पर इनमें से कोई भी देश की अखंडता की मांग कर सकता है।

हमने अपनी शर्त पूरी कर दी है और अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। चार करोड़ मुसलमानों की रक्षा करने के लिए हिंदुस्थान का प्रत्येक दल तैयार है परंतु पाकिस्तान ने इस शर्त को पूरा नहीं किया। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं पर किया गया बर्बर अत्याचार ही प्रमाण के लिए पर्याप्त है। पंडित नेहरू इसके लिए आज क्या कर रहे हैं? सरदार पटेल तो सांप्रदायिक नहीं थे, उन्होंने भी कहा था निर्वासितों को रखने के लिए आधा बंगाल पाकिस्तान से मांगा जाएगा। आज इस प्रश्न को नेहरूजी क्यों नहीं रखते?

किंतु यह अखंडता किसी आक्रमण से नहीं प्राप्त होगी। यह समस्या का ठीक हल नहीं है। वह तभी होगा जब यहां का हिंदू और यहाँ का मुसलमान इन बातों को समझ लेगा कि उसका भला इसी में है और यह विचार दिनों दिन जोर पकड़ते-पकड़ते एक दिन यह संभव हो जाएगा।

विचारों के ही कारण भारत बँटा है, विचारों से ही यह एक होगा। हमारी दूसरी मर्यादा एक राष्ट्र में विश्वास है। हम मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद को नहीं मानते। हमारा कहना यह है कि यदि फारस, चीन और तुर्की का मुसलमान अपने धर्म को मानता हुआ अलग अलग राष्ट्रीयता मानता है तो भारत का मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उन देशों में लोग अपने देश की भाषा और संस्कृति को मानते हैं। यहाँ भी मुसलमानों को इस देश की संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिंदी को मानना चाहिए। ▪

» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 घंटे में सर्वाधिक पौधे लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने टीकमगढ़ में श्री सदाशिव प्रतिमा का लोकार्पण किया।

» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया।

» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल एवं संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने डॉ. मुखर्जी जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया।

» प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने केन्द्रीय बजट पर लोकसभा में केन्द्र सरकार का पक्ष रखा।

» मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया।

» भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति बैठक में वरिष्ठ नेतागणों ने भाग लिया।

» अमरवाड़ा की जीत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

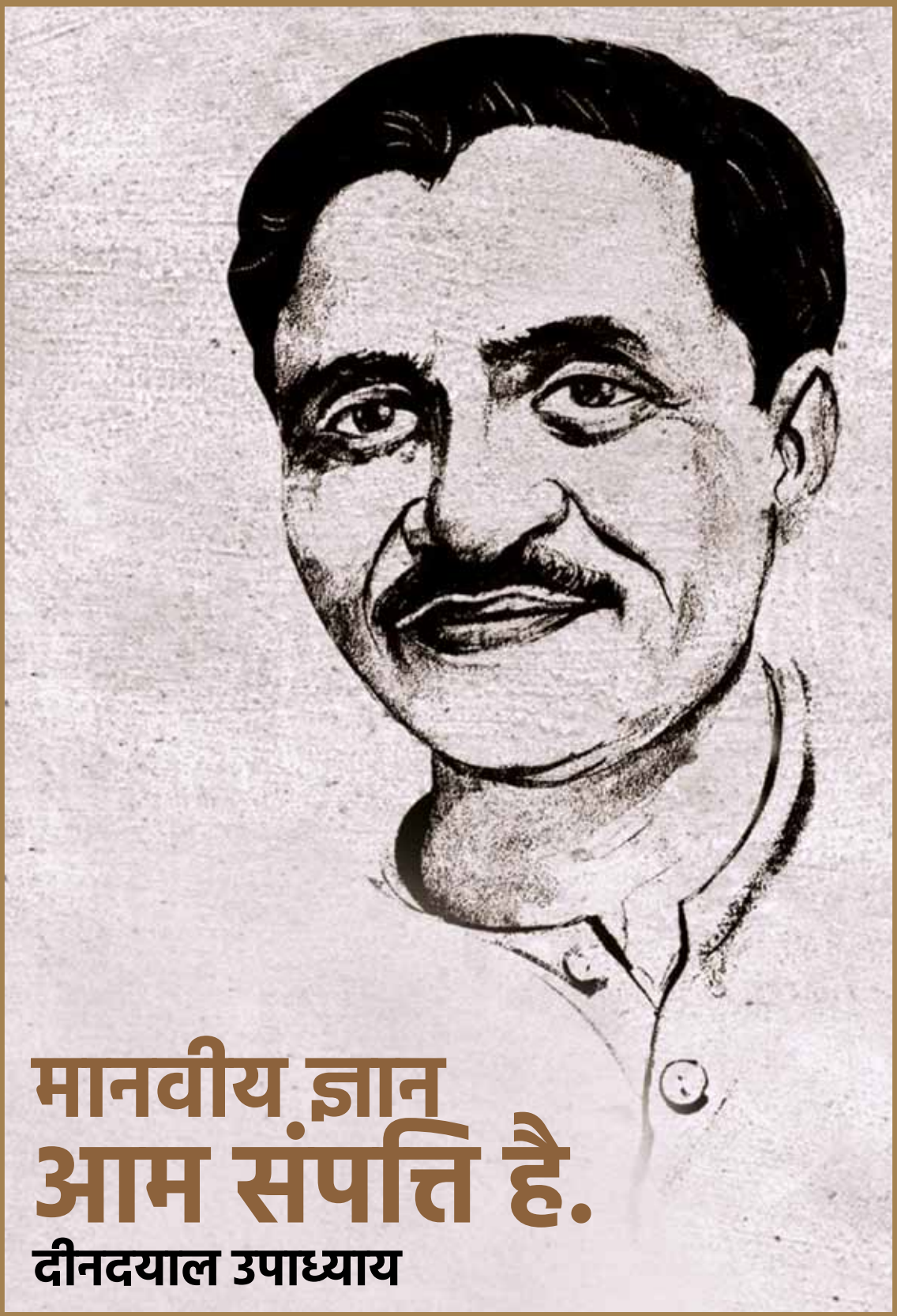

मानवीय ज्ञान आम संपत्ति है.

दीनदयाल उपाध्याय